www.dainikjayantnews.com
कोटद्वार, शनिवार
11 जुलाई 2026
वर्ष: 49
अंक: 74 पृष्ठ: 6
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

पुरी के राजा का राष्ट्रपति और पीएम को पत्र

कहा-इस्कान का अलग समय पर रथयात्रा निकालना गलत

भुवनेश्वर (एजेंसी)। पुरी के गजपति महाराज दिव्यसिंह देव ने इस्कान की तरफ से अलग तिथियों पर जगन्नाथ रथयात्रा और स्नान यात्रा निकालने पर आपत्ति जताई है। दिव्यसिंह देव ने 8 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है और हस्तक्षेप की मांग की है। दिव्यसिंह ने कहा कि इससे प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। गजपति महाराज दिव्यसिंह देब श्रीजगन्नाथ मंदिर

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस्कान रथयात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं हैं। इससे भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। **इस्कान ने विदेशों में पहले मनाया उत्सव**- इस्कान ने 21 जून को लंदन, 14 जून को न्यूयॉर्क सिटी और 5 जुलाई को सिडनी में रथयात्रा निकाली थी। लेकिन इस साल, स्नान पूर्णिमा 29 जून को थी और पुरी में मुख्य रथयात्रा 16 जुलाई को होगी। इस्कान का कहना है कि भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के हैं। विदेशों में मौसम, स्थानीय परिस्थितियों और भक्तों की सुविधा को देखते हुए रथयात्रा की तारीखें अलग-अलग होती हैं ताकि ज्यादा लोग उत्सव में शामिल हों और जगन्नाथ संस्कृति का वैश्विक प्रसार हो।

टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल

पार्टी ने तीनों को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने तीनों को बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने

राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। तीनों ने ममता से नाराजगी जताई थी और कहा था कि पार्टी मनमाने ढंग से चल रही है। सुखेंदु ने 8 जून, सुष्मिता ने 10 जून और प्रकाश ने 11 जून को रिजाइन दिया था। बंगाल की इन तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को वोटिंग और काउंटिंग होगी। 14 जुलाई तक नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी।

तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद करूर पहुंचे विजय

बोले-भगदड़ में हमने अपनी बहनों के बच्चों को खो दिया

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय शुक्रवार सुबह करूर पहुंचे। वे हाल ही में करूर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र और कल्याणकारी सहायता प्रदान करने पहुंचे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यहां 2025 में हुई भगदड़ की घटना को लेकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। उस हादसे में हमने अपनी बहनों के बच्चों को खो दिया। मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह हवाई मार्ग से चेन्नई से रवाना हुए और उनके तिरुचिरापल्ली (तिरुची) हवाई अड्डे पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से करूर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पूरे मार्ग पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत की तैयारियां की गईं। विजय करूर-सेलम बाइपास रोड स्थित एटलस कलैयारंगम मैदान पहुंचने से पहले लगभग 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद वह वहां आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।

बारिश की वजह से कब्रों से बाहर निकल आए मुर्दे!

सहारपुर (एजेंसी)। मानसून की पहली धमाकेदार बारिश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को जमकर कोहराम मचाया। एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद और नोएडा की सड़कें लगभग थम सी गईं। गाड़ियों के जाम ने दोनों शहरों की रफ्तार को रोक दिया। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पेड़ गिरे, आलम ये रहा है कि कुछ घंटों की बारिश ने अकेले गाजियाबाद में 6 लोगों की जान ले ली। लेकिन, वेस्ट यूपी के सहारनपुर में इस बारिश ने वो किया, जिसे जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यहां भारी बारिश की वजह से पानी भरने के बाद मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल गए। मामला सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी इलाके में पड़ने वाले सैय्यद माजरा गांव का है। यहां हाईवे के किनारे पर एक कब्रिस्तान बना हुआ है। गुरुवार को भारी बारिश होने की वजह से कब्रिस्तान में भी पानी भर गया और कई जगहों पर मिट्टी धंस गई। जलभराव से कई कब्रों को नुकसान पहुंचा और दफन हुए कुछ शव कफन सहित बाहर दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई

यूपी के सहारनपुर में हड़कंप,सुनकर तुरंत दौड़े गांव वाले

और हड़कंप मच गया। गांव के लोग बड़ी संख्या में कब्रिस्तान पहुंचे और सबसे पहले शवों को सम्मानपूर्वक सुरक्षित जगहों पर रखवाया। इसके बाद जब बारिश थम गई, तो कब्रिस्तान का पानी निकाला गया और इन शवों को दोबारा दफनाने की व्यवस्था की गई। गांव के लोगों का कहना है कि बारिश पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही है। हाईवे किनारे बने नालों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम ना होने की वजह से कब्रिस्तान में भी पानी भर गया था और इस वजह से शव बाहर आ गए। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन के सामने गुहार लगाई है कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जल निकासी के उचित इंतजाम किए जाएं। वहीं, मौसम की अगर बात करें तो मानसून अभी एक्टिव है और 11 जुलाई को भी वेस्ट यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं।

अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक

● 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी

कफ सिरप और टॉनिक पर असर,ड्रग रूल्स 1945 में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में यह बदलाव किया है। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को 'शेड्यूल एच 1' कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 12 फीसदी से ज्यादा होती है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती हैं।

मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा

मेडिकल स्टोर्स के लिए भी खास निर्देश हैं। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा। मार्केट में मिलने वाले कई कफ सिरप और टॉनिक में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। बिना रोक-टोक या डॉक्टर की पर्ची के मिलने से कई लोग इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगे थे। इसी दुरुपयोग को रोकने और दवाओं की बिक्री की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स

हालांकि, जर्नल ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसी दवाओं का बिना डॉक्टरी सलाह के या जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए, तो यह बच्चों, बुजुर्गों और लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इस कदम से भारत में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम और मजबूत होगा। दवाओं की ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी यानी यह पता लगाना आसान होगा कि कौन सी दवा कहां और किसे बेची गई। इससे दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सरकार ने भी माना कि ई20 पेट्रोल से माइलेज पर असर

इथेनॉल विवाद के बीच आया नितिन गडकरी का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में ई20 फ्यूल, यानी पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। देशभर की जनता माइलेज ड्रॉप होने और परफॉर्मेंस प्रभावित होने के साथ ही इंजन में कथित खराबी को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं।

बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप के दावों ने जैसे आग में घी का काम किया और जब विवाद ज्यादा गहरा गया तो अब केंद्र की मोदी सरकार के एक अहम बाद स्वीकार की है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि ई20 पेट्रोल से माइलेज पर हल्का असर होता है, लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आती।

माइलेज पर मामूली असर- केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि इथेनॉल का कैलोरिफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होता है, जिसके कारण माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है। यह प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है।

पहली बार नजर आ सकते हैं नए सुप्रीम लीडर मुजतबा

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वे कोम शहर की हजरत मासूमेह दरगाह में अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शोकसभा की अगुवाई करेंगे। शुक्रवार को अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा के रौजे में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इसके अगले दिन कोम में यह शोकसभा आयोजित की जा रही है। मुजतबा के सार्वजनिक रूप से सामने आने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। शुरुआती मार्च में धार्मिक परिषद ने मुजतबा को नया सुप्रीम लीडर चुना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फरवरी में हुए हमले में वे घायल हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा कारणों से वे अब तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। हालांकि, इन देशों ने कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस से जुड़े एक रणनीतिक रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका-ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही गुरुवार को ठप रही। इससे वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1त्न की बढ़ोतरी हुई। अल जजीरा के मुताबिक, ईरान ने एक ही रात में कम से कम 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात के लिए भेज दिया।

ईरानी मीडिया का दावा-
पिता खामेनेई की शोकसभा में शामिल होंगे

राजपाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा

● दिल्ली हाईकोर्ट का चेक बाउंस केस में बड़ा फैसला ● जुर्माना भी लगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्टर पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को संदिग्ध बताया और अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में एक्टर का रवैया संदिग्ध रहा है।

मामला साल 2010 का है, जब 5 करोड़ का कर्ज लिया था- यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और इसके बाद वह तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाए।

उच्च शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, रोजगार सहित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

एआईसीटीई मानकों के अनुरूप पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के समुचित विकास के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम तथा आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित विश्वस्तरीय शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता, उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी

राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026" के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई।

राज्य भण्डारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के नियमित 68 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी लेखा परीक्षा के लिए दो पदों का सृजन

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित कुल दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और अधिक सशक्त

राज्य में वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन तथा दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे उत्तराखण्ड के युवा

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन हेतु सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (ढटव) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण एवं नियोजन से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त

राज्य में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से "अरेबिया मदरसों को अनुदान" संबंधी बजट मानक मद को समाप्त (विलोपित) किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे। कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ विकास एवं जनकल्याण के प्रयास और अधिक प्रभावी होंगे।

उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग दें उद्योग समूह : धामी

उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग' कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों, विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारियों, सीएसआर पार्टनर्स, उद्योग एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तीर्थ स्थलों पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए कॉरपोरेट समूहों द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में, सीएसआर के तौर पर दिए गए योगदान का महत्व भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत से समूह सीएसआर के तहत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में स्थापित अन्य समूहों से भी अपना सीएसआर उत्तराखंड में ही खर्च करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई औपचारिक

बैठक नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साझा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने उद्यमी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी ह्वइन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेटह्व के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट कुशलता और प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियां मिलकर एक ऐसी सस्टेनेबल इकोनॉमी का निर्माण करेंगी, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव विनय शंकर पांडेय, एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार, अपर सचिव मनमोहन मैनाली शामिल हुए।

इनके साथ हुआ एमओयू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आयोजन में कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए किए गए हैं। साथ ही देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों ने उत्तराखंड के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की है। इस मौके पर हुंडई, लर्नेंट-इंफोशिस फाउंडेशन, ओएनजीसी, आईटीसी, महेंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स, पैनोसोनिक के एमओयू किया गया।

केसी वेणुगोपाल ने की प्रेसवार्ता

कहा—उत्तराखंड कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं

देहरादून : दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज देहरादून में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस में कोई गुट बाजी बड़ी नहीं है। सभी नेता एकजुट होकर चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, लोग इस बार सरकार बदलने को तैयार हैं। चुनाव से पहले जनता कांग्रेस के बीच जाएगी। मेनिफेस्टो कमेटी, हर वर्ग से बात करेंगे। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया। कहा कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले अब चढ़ावा चोरी भी करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया था, लेकिन चढ़ावा चोरी पर आज मौन हैं।

एक नजर

ग्रामीणों ने किया नलकूप खंड कार्यालय का घेराव

रायवाला। धान की रोपाई के लिए पानी नहीं मिलने से नाराज रायवाला गांव के काश्तकारों ने ग्राम प्रधान सागर गिरि के नेतृत्व में प्रतीत नगर स्थित नलकूप खंड कार्यालय का घेराव किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है।

इन दिनों काश्तकार धान की रोपाई में लगे हैं। लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के रायवाला स्थित नलकूप खंड में पंप बंद होने से किसानों की समस्या और अधिक बढ़ गई है।

बृहस्पतिवार को रायवाला के ग्रामीणों ने अपनी यह समस्या ग्राम प्रधान सागर गिरि को बताई। जिसके बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीण रायवाला स्थित नलकूप खंड कार्यालय पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में खराबी आने के कारण पंप संचालित नहीं हो पा रहा है।

नीलकंठ मोटर मार्ग पर आया मलबा, यातायात बाधित

यमकेश्वर। नीलकंठ मोटर मार्ग पर शुक्रवार को बारिश के बाद कई जगह मलबा आने से यातायात बाधित रहा। सड़क पर दलदल जमा होने से पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नीलकंठ में कैथल धर्मशाला के समीप सुबह सड़क पर आए मलबे से दलदल बन गया। इसी दलदल में सुबह एक गाय फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने गाय को बाहर निकाला। सड़क पर दलदल बनने से वाहनों का संचालन बंद रहा। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था।

दिनभर जेसीबी मशीन मलबा साफ करने में जुटी रही। वहीं खैरखाल के समीप सड़क पर चट्टान गिरने से यातायात कुछ देर के लिए पूरी तरह बंद रहा। जेसीबी मशीन से मलबा साफ कर यातायात सुचारु किया गया। मोटर मार्ग पर मलेलगांव, पीपलकोटी, खैरखाल, कालीकुंड, रत्तापानी, फूलचट्टी, गरुड़चट्टी आदि स्थानों पर फिसलन बनने से बाइक फिसलने की आशंका बनी रही। कई दुपहिया सवार गिरते-गिरते बचते दिखे।

सड़कों से हटाए गए 60 गोवंश

ऋषिकेश। आगामी कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद मुनि की रेती-ढालवाला ने सड़कों से निराश्रित गोवंश हटाने का अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार तक 60 गोवंशों को पकड़कर गोशाला भेजा जा चुका है।

शुक्रवार को पालिका की टीम ने रामझूला और ढालवाला क्षेत्र में निराश्रित गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान कैटल कैचर की मदद से निराश्रित गोवंशों को पकड़कर देहरादून स्थित गोशाला भेजा गया।

अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यह अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। अब तक 60 निराश्रित गोवंशों को सुरक्षित रूप से गोशाला भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी रहेगा और जल्द ही नगर क्षेत्र को सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंशों से मुक्त कराया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिल सके।

दीन-दुखियों की सेवा से मिलता है पुण्य

गुप्तकाशी। कालीमठ क्षेत्र के कोटि माहेश्वरी मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा के दसवें दिन शुक्रवार में भक्तों ने कथा का श्रवण किया। कथावाचक आचार्य संजय कृष्ण ने शिव महापुराण कथा का वाचन करते हुए कहा कि जो मानव शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है उसे स्वयं भगवान शिव अपने धाम में स्थान देते हैं। प्रभु के स्मरण के साथ-साथ मनुष्य को अपने जीवन में दीन-दुखियों की सेवा और सहायता करने से भी पुण्य मिलता है। इस अवसर पर आचार्य विपिन भट्ट, आयुष भट्ट, पुरुषोत्तम दत्त, मुलायम सिंह, दिलीप सिंह, दिनेश, विशंभर दत्त भट्ट आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे।

टीईटी से छूट और पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

रूड़की। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, रुड़की के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रवार को वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने तथा सभी शिक्षक कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की एवं उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा।

ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य की गई। उन्होंने कहा कि अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को उन्होंने अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध किया। शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से संसद के मानसून सत्र में विशेष अध्यादेश लाकर 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने और सभी शिक्षक कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। इस दौरान पंकज कुमार विश्नोई, रेणु रानी, शालिनी गौस्वामी, राजीव शर्मा, अजय सिंह पुंडीर सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे।

टिहरी लेक ग्लोबल डेस्टिनेशन को लेकर हुई हाई पॉवर कमेटी की बैठक

उत्तराखंड का क्राफ्ट, कल्चर, हेरिटेज को लेकर ट्रेडिशनल विलेज किया जाए तैयार

देहरादून : मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में टिहरी झील को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी लेक ग्लोबल डेस्टिनेशन से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में एमडी टीएचडीसी को स्पेशल इनवाइटी के रूप में डीएम टिहरी को भी शामिल किया जाए। साथ ही, टिहरी लेक प्रोजेक्ट को एक कैची सा नाम दिया जाए, जो लोगों की जुबान पर बस जाए और बोलना आसान हो। मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के साथ ही टिहरी लेक प्रोजेक्ट को अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली एसटीपी को भी सोलर पॉवर से संचालित किए जाने हेतु सोलर

प्लांट लगाए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी लेक के आसपास कुछ गांवों को उत्तराखण्ड के क्राफ्ट, कल्चर, हेरिटेज की थीम से जोड़ते हुए ट्रेडिशनल विलेज के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने इस प्रकार के मॉडल विलेज को आजीविका से जोड़ते हुए लोकल हितधारकों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट हमें सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स के लिए लागू करना चाहिए।

मुख्य सचिव ने योजना के तहत् बनायी जाने वाली प्रत्येक सम्पत्ति के संचालन एवं रखरखाव की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए योजना में हितधारकों को जोड़ते हुए आय सृजन गतिविधियों को शामिल किया जाए। उन्होंने टिहरी झील में बोटिंग और जेटी के संचालन के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर झील की क्षमता का आंकलन करते हुए सम्पूर्ण कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि काम फेजवाईज किया जा सकता है, परन्तु सम्पूर्ण योजना एक बार में तैयार की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने म्यूजियम की थीम का निर्माण टिहरी क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए की जाए। उन्होंने कहा कि पुरानी टिहरी का राजशाही इतिहास, लोककला एवं लोकसंस्कृति सहित पुरानी टिहरी का 3डी मॉडल भी शामिल किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री दिलीप जावलकर, डॉ. वी. षणमुगम एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेलवे निर्माण कंपनी के बैचिंग प्लांट में लगी आग

रुद्रप्रयाग। घोलतीर-नगरासू के पास रेलवे निर्माण कार्य में लगे बैचिंग प्लांट में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। आग लगते ही प्लांट से ऊंची लपटें उठने लगीं। हालांकि कंपनी के कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, रेलवे निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला बैचिंग प्लांट दिनभर संचालन के बाद शाम करीब पांच बजे बंद किया जा रहा था। इसी दौरान प्लांट के बेस हिस्से को गैस वेल्डिंग से काटने का कार्य किया जा रहा था। तभी अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आरवीएनएल के उप महाप्रबंधक (सिविल) ओ.पी. ने बताया कि गैस वेल्डिंग के दौरान प्लांट के बेस में आग लग गई थी। कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और करीब आधे घंटे में स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

बारिश के बीच घर पर आफत बन गया पेड़

तीन लोग आधे घंटे तक फंसे रहे

नैनीताल ,शहर के न्यू पैवेलियन होटल के पास बृहस्पतिवार रात घर पर विशालकाय पेड़ गिरने से लोगों में अफरातफरी और चीखपुकार मच गई। हादसे में दो लोग घायल हो गए। बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एसडीआरएफ के एसआई मनोज भाकुनी ने बताया कि बारिश के दौरान रात करीब आठ बजे घर पर पेड़ गिरने की सूचना मिली। पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कुछ लोग समय रहते बाहर निकल गए थे जबकि तीन लोग आधे घंटे तक घर में फंसे रहे।

घटना में घायल अब्दुल वाशिद (58), दीवान आर्या (32) का बीडी पांडे अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू टीमों ने घर की चहारदीवारी पर गिरे पेड़ को हटाया। तब जाकर लोगों ने घर में शरण ली।

नैनीताल में रातभर झमाझम बारिश, नाले उफान पर, कोहरे से थमी रफ्तार

सरोवर नगरी नैनीताल में बुधवार रात करीब आठ बजे से शुरू हुई मूसलधार बारिश बृहस्पतिवार सुबह तक जारी रही। लगातार हुई बारिश से शहर के नाले उफान पर आ गए और कई स्थानों पर पानी का बहाव तेज हो गया। शहर में बीते 24 घंटों में 119 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

11 जुलाई से परेड मैदान में होगा 'लोक संवर्धन पर्व', केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे शुभारंभ

देहरादून : भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 11 से 15 जुलाई तक देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व के छठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। पांच दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन शनिवार 11 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय व उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। यह महोत्सव 15 जुलाई तक आम जनता के लिए निशुल्क खुला रहेगा।

देहरादून में आयोजित होने वाला यह संस्करण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किसी राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तराखंड, प्रधानमंत्री विरासत

का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत इस प्रमुख आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल पारंपरिक कला, शिल्प एवं पाक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूत करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्ष 2024 में शुरुआत के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के सहयोग से लोक संवर्धन पर्व के पांच सफल संस्करण आयोजित किए हैं, जिनसे 550 से अधिक कारीगरों और पाक विशेषज्ञों को लाभ मिला है। यह महोत्सव विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, पाक विशेषज्ञों एवं उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार, व्यापार विकास तथा पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करता है।

चार जिलों में ऑरेंज, तीन में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 115 सड़कें अवरुद्ध,

देहरादून : मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूएसनगर, नैनीताल और चंपावत के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से सबसे गंभीर स्तर की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से इन सातों जिलों में प्रशासन को तत्काल एहतियाती कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे पूरे उत्तराखंड में खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में और नदी-नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सात जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इसके

अलावा बाकी जनपदों में भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

प्रदेश में बारिश ने बरपाया कहर, 115 सड़कें बंद

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सड़कों पर मलबा आने से कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 115 सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग बोल्डर गिरने से बंद है। इसके अलावा जिले में 12 ग्रामीण मार्ग भी बंद हैं। जबकि देहरादून में एक राज्य और 14 ग्रामीण मार्ग, अल्मोड़ा में 13 ग्रामीण मार्ग, रुद्रप्रयाग में तीन, चमोली में नौ, नैनीताल में पांच, उत्तरकाशी और बागेश्वर में चार-चार और टिहरी में एक राज्य और 13 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। बंद सड़कों में सबसे अधिक 31 सड़कें पौड़ी जिले की हैं। इसमें दो राज्य मार्ग, एक मुख्य मार्ग और 28 ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं।

आपदा के एक माह बाद भी सुरक्षा कार्य न किए जाने पर गुस्साए

जखोली। गत 10 जून को अतिवृष्टि के कारण खलियान गांव के खूड़गड़ गदेरे में आए मलबे व पानी से मची तबाही के एक माह बाद भी सुरक्षा कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जुलाई माह में संपर्क मार्गों और खूड़गड़ गदेरे पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल करेंगे।

ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी ने बताया कि आपदा को एक माह बीत जाने के बाद भी सिंचाई विभाग ने केवल गांव से ऊपर खूड़गड़ गदेरे पर लस्तर-हिलाईं नहर के पीलर को सुरक्षित किया है जबकि गांव की सुरक्षा के लिए मुख्य सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य ललिता देवी ने कहा कि रुद्रप्रयाग विधायक व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और ब्लॉक प्रमुख जखोली विनीता चमोली ने मौके पर पहुंचकर गांव के पैदल मार्गों का निर्माण और मलबे का सुरक्षित निस्तारण कराने का भरोसा दिया था लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस सुस्ती से परेशान ग्रामीण रघुवीर सिंह राणा, रमेश सिंह बिष्ट, प्रकाश लाल, सुखवीर सिंह जाखी व रमेश चंद्र भट्ट ने जुलाई माह में सुरक्षा कार्य शुरू न होने पर भूख हड़ताल और प्रदर्शन की चेतावनी दी।

वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती में युवाओं को राहत : नियमों में भी किया गया बदलाव

देहरादून : प्रदेश में अलग-अलग वर्दीधारी सिपाही के पदों पर भर्ती के मानकों में सरकार ने फिलहाल तीन साल तक राहत दे दी है। एकीकृत नियमावली के हिसाब से तय अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का नियम अब 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगा। तब तक पुराने मानकों के हिसाब से ही भर्तियां होंगी।

पूर्व में सरकार ने इन पदों के लिए एकीकृत नियमावली बनाते हुए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की थी, जिस कारण तमाम ऐसे बेरोजगार युवा भर्तियों से बाहर हो रहे थे, जिनकी आयु इससे अधिक हो चुकी है। अब उप निरीक्षक (पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर (पीएसी, आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और वन दरोगा के पदों को छोड़कर, अन्य विहित पदों पर 31 दिसंबर 2028 तक सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार विशेष रियायत दी जाएगी। एक जनवरी 2029 से सभी पदों पर 35 वर्ष का नियम समान रूप से प्रभावी हो जाएगा। आरक्षित वर्ग को नियमावली छूट मिलती रहेगी।

इन विभागों में सिपाही भर्ती में मिलेगी राहत

- अग्निशामक (गृह विभाग)
- बन्दी रक्षक (गृह विभाग)
- वन आरक्षी (वन विभाग)
- आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)
- प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)

शारीरिक मानक भी जारी

नए नियमों में अलग-अलग पदों के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और सीने की माप के कड़े मानक तय

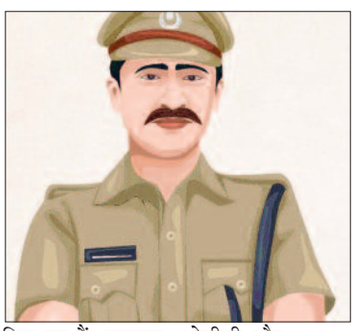

किए गए हैं। सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई पद के अनुसार 163 सेमी से 167.7 सेमी तक अनिवार्य की गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और एसटी वर्ग को नियमों में विशेष छूट दी गई है। सभी विभागों में महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर गतिविधि को अनिवार्य रूप से पास करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक में भी फेल होगा तो वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। बता दें कि क्रिकेट बॉल थ्रो और लंबी कूद में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग दूरी तय की गई है। कई पदों के लिए पुरुषों को कम से कम पांच बार बीम खींचना अनिवार्य होगा। वन दरोगा पद के लिए पुरुषों को चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पुलिस और अन्य विभागों के लिए 5 किलोमीटर (पुरुषों के लिए 32 मिनट में) और 2 किलोमीटर (महिलाओं के लिए 15 मिनट में) की दौड़ रखी गई है। 25 गुना 4 मीटर की शटल रेस को 30 सेकंड के भीतर पूरा करना होगा।

महिलाओं ने खेतों में की धान की रोपाई

अगस्त्यमुनि। नगर पंचायत क्षेत्र के नाकोट गांव में बारिश के बाद खेतों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। पर्याप्त वर्षा होने पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से धान की रोपाई शुरू कर दी है। आचार्य अनिल बेंजवाल ने बताया कि लंबे समय तक बारिश नही होने और बढ़ रही गर्मी के कारण रोपाई का कार्य प्रभावित हो गया था। समय पर बारिश होने से अब खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है जिससे रोपाई का कार्य शुरू हो सका। उन्होंने कहा कि सामूहिक श्रम की यह परंपरा खेती को बढ़ावा देती है और ग्रामीण संस्कृति व आपसी सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है। रोपाई में सुमन देवी, माधुरी देवी, सोनी देवी, पूजा देवी, पार्वती देवी, सीमा देवी, प्रतिमा देवी, उत्तरा देवी, शमा मलासी आदि महिलाएं शामिल हुईं।

एक नजर

पारस बलोधी का नवोदय विद्यालय में चयन

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : दुगड्डा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झटरी (आठवीं उत्तीर्ण) के छात्र पारस बलोधी का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, खैरासैंण (पौड़ी गढ़वाल) में कक्षा 9 के लिए हुआ है। इससे पहले पारस कक्षा 6 में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। पारस की माता बैजंती बलोधी विद्यालय में भोजन माता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बेटे की सफलता का श्रेय उसकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विवेकानंद, शिक्षक चंद्र मोहन थपलियाल और सुरदीप गुसाईं ने पारस को बधाई देते हुए इसे सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया।

शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

देवप्रयाग : उत्तराखंड राज्य राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा देवप्रयाग ने टीईटी से छूट देने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए उपशिक्षा अधिकारी भास्कर बेबनी के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। शिक्षकों ने जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। ताकि सभी शिक्षक बिना किसी मानसिक तनाव सहित अधिक निष्ठा व लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। ज्ञापन देने वालों में संगठन के अध्यक्ष राकेश बागड़ी, महामंत्री कुशल सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष दीवान सिंह सहित देवप्रयाग ब्लॉक के बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षक व कार्यकारिणी के सदस्य शामिल थे। (एजेंसी)

गंदगी फैलाने वालों पर हो कार्रवाई की उठाई मांग

श्रीनगर गढ़वाल : नगर निगम के वार्ड संख्या-28 आम्रकुंज के पार्षद जेपी बिष्ट ने ऐठाणा गांव जाने वाले मार्ग और रोटरी क्लब की ओर से लगाई गई कुर्सियों पर फैलाई जा रही गंदगी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व रात के समय यहां शराब पीकर खाने-पीने का सामान और खाली बोतलें खुले में छोड़ रहे हैं। यह स्थान प्रकृति के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है लेकिन कुछ लोगों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें इसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से कूड़ा संग्रहण वाहन नियमित रूप से क्षेत्र में पहुंच रहा है इसके बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंका जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने की भी मांग की। (एजेंसी)

लंबित परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने छात्र हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) से मुलाकात की। उन्होंने लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान करने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट ने ज्ञापन में बीटेक प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोलकर अंतिम अवसर देने, सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूजी पंजीकरण पोर्टल शीघ्र शुरू करने, प्रथम सेमेस्टर सहित सभी लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा यूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने आदि की मांग की। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा, पंकज फर्स्वाण, सारांश, आयुष, रोहित, शेखर, संजय आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

यूपी की यात्रा पर निकलेंगे देवप्रयाग के मेधावी छात्र

श्रीनगर गढ़वाल : देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की पहल पर मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित होने वाले ह्यभारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम-2026ह्ल की रूपरेखा जारी कर दी गई है। विधायक द्वारा पिछले 9 वर्षों से निजी खर्च पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 15 से 20 सितंबर तक हाईस्कूल के टॉपर छात्र उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रमुख स्थलों का शैक्षिक भ्रमण करेंगे।

श्रीनगर जीएमवीएन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराना है। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होगी जहां विद्यार्थियों को गंगा आरती के दर्शन कराए जाएंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती के बाद छात्र उत्तराखंड विधानसभा का भ्रमण करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे। इसके बाद दल उत्तर प्रदेश जाएगा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट, यूपी विधानसभा व तारामंडल का अवलोकन और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन शामिल हैं। दल की वापसी 20 सितंबर को नई दिल्ली से होगी। विधायक ने इसे व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय चेतना का सार्थक प्रयास बताया। इस अवसर पर कुलदीप, वासुदेव भट्ट, नरेंद्र कुंवर, अमरजीत सिंह, देवेंद्र बुटोला, आकाश रावत, दीपक राणा और नरेश नेगी आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

महिलाओं ने सीखे दुग्ध उत्पादों के निर्माण की तकनीकी गुर

श्रीनगर गढ़वाल : विकासखंड पौड़ी से ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना की ओर से अंगीकृत साधना सहकारिता एवं प्रेरणा सहकारिता से जुड़ी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 30 महिलाओं ने आंचल डेयरी का भ्रमण किया। प्रयोगशाला सहायक एवं सहायक प्रभारी दुग्ध नियंत्रक मनमोहन सिंह ने महिलाओं को दुग्ध संग्रहण (मिल्क कलेक्शन), दूध की गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, विभिन्न रसायनों के सुरक्षित उपयोग तथा डेयरी में प्रयुक्त मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। महिलाओं ने दूध से तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को भी निकट से देखा और प्रशिक्षण लिया। साथ ही महिलाओं को गोबर से जैविक खाद तैयार करने की बताई गई। कार्यक्रम में पूंदोरी, गहड़, नीनारा, थपलियाल गांव, निसणी, जेराज आदि गांवों की महिला समूह सदस्य शामिल रहीं। इस दौरान सहकारिता स्टाफ से सुमित्रा बुटोला, रेशमी, साक्षी, नम्रता, जमुना नेगी, पूनम देवी, योगेश एवं किरण उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें धीमे निस्तारित होने पर डीएम खफा

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विभागों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है।

पहली ही बरसात में उखड़ी इंटरलॉकिंग सड़क, कौड़िया-दिल्ली फार्म मार्ग पर बढ़ा हादसों का खतरा

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः कौड़िया चौराहे से दिल्ली फार्म को जोड़ने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क पहली ही बरसात में बदहाली की भेंट चढ़ गई है। तेज बारिश के दौरान हुए पानी के बहाव में सड़क के किनारों की मिट्टी कटने से अधिकांश इंटरलॉकिंग टाइल्स उखड़कर बह गई हैं। इसके चलते पूरा मार्ग रेखड़ और बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, जबकि भारी वाहनों का आवागमन इस खतरे को और बढ़ा रहा है। यह मार्ग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। कुछ माह पूर्व संबंधित विभाग ने सड़क की मरम्मत कर यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई थीं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पहली ही बरसात की परीक्षा में टिक नहीं पाई। तेज बहाव के कारण सड़क के किनारों का कटाव शुरू होते ही इंटरलॉकिंग टाइल्स जगह-जगह धंस गईं और कई स्थानों पर पूरी तरह बिखर गईं। सड़क पर फैली टूटी-फूटी टाइल्स के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर बारिश का पानी सीधे सड़क के बीच से बह रहा है, जिससे गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते और दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस

कोटद्वार में बदहाल पड़ा कौड़िया से दिल्ली फार्म को जाने वाला मार्ग

मार्ग पर डामर की सड़क थी, जिससे आवागमन सुगम रहता था। बाद में डामर सड़क हटाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा दी गईं, जो पहली ही बरसात में उखड़ गईं। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि वर्षाकाल में लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

क्षेत्र में जानवरों की धमक पर दिखाएं गंभीरता

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : सनेह क्षेत्र के ग्रास्टनगंज में हाथियों के लगातार आबादी में घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने प्रभागीय वनाधिकारी लैंसडौन वन प्रभाग को ज्ञापन भेजकर हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सिद्धबली मंदिर से ग्राम सनेह तक का क्षेत्र हाथी कोरिडोर में आता है, जिसके कारण वार्ड नंबर-1 ग्रास्टनगंज सहित आसपास के इलाकों में लंबे समय से हाथियों का खतरा बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से 30 से 35 हाथियों का झुंड लगातार आबादी में प्रवेश कर रहा है। हाथियों ने ज्योति रावत के घर का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर घुसते हुए तोड़फोड़ की। परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। यूकेडी का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार वन विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नही की गई। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्र में नियमित गश्त कर हाथियों को आबादी से दूर रखने की मांग की है।

80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स का होगा सम्मान

कोटद्वार : गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में गोल्डन कार्ड व्यवस्था, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति और पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिक कार्यालय में आयोजित बैठक का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष जयवीर सिंह रावत ने किया। बैठक में सदस्यों ने गोल्डन कार्ड योजना के संचालन, एकमुश्त दी गई राशि में की जा रही कटौती तथा इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि यदि सेवारत अथवा पेंशनर्स कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च में वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त राशि का वहन सरकार को स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड व्यवस्था लागू होने से पहले भी कर्मचारियों के इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही की जाती थी, इसलिए इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। बैठक में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पेंशनर्स को आयु आधारित अतिरिक्त पेंशन लाभ देने का भी सुझाव रखा गया। सदस्यों ने मांग की कि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलने वाली 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के बजाय 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्रमशः 5-5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था लागू की जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र पंत, चित्रमणि देवलियाल, भारत भूषण रावत, हरीश कुंडलिया, सुनील नवानी, जेपी ध्यानी, केसीराम निराला, इंद्रमणि देवरानी, शिवर सिंह, बृजेंद्र सिंह और दिनेश चंद्र नेगी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को

श्रीनगर गढ़वाल : तहसील विधिक सेवा समिति श्रीनगर ने हरेला पर्व और विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में शुक्रवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष कुमारी अलका की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई को हरेला पर्व पर व्यापक स्तर पर पौध रोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा 18 जुलाई को होने वाली होगी लोक अदालत को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित अधिक से अधिक वादों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने पर जोर दिया गया।

कोटद्वार में लाखों की स्मैक के साथ हरिद्वार के दो युवक गिरफ्तार

कोटद्वार पुलिस की हिरासत में स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : कोटद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से कोटद्वार स्मैक बेचने आए थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। शुक्रवार सुबह पुलिस टीम कौड़िया रेलवे फाटक क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मजार के निकट दो युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते दिखाई दिए। पुलिस को अपनी ओर आते देख दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा निवासी सोहेल पुत्र मांगा हसन और साहिब पुत्र कप्यूम के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से 60-60 ग्राम, कुल 120 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से स्मैक लेकर कोटद्वार में बेचने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के अनुसार, मुरादाबाद में आरोपियों को स्मैक किसने उपलब्ध कराई और कोटद्वार में वे किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पहाड़ की ऊंचाईयों तक पहुंचा हाथी, भंवासी क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत करीब तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित भंवासी क्षेत्र में पहली बार हाथी की मौजूदगी दर्ज की गई है। अब तक गुलदार, भालू और जंगली सूअर के आतंक से जूझ रहे ग्रामीणों के सामने हाथी की आमद नई चुनौती बनकर उभरी है।

पौखाल और भंवासी गांव के आसपास हाथी के विचरण की सूचना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को जान-माल के साथ ही फसलों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

अब तक हाथियों की गतिविधियां मुख्य रूप से लैंसडौन वन प्रभाग के मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रहती थीं। कोटद्वार के रामणी-पुलिंडा मार्ग, सनेह क्षेत्र, भाबर इलाके, कोटद्वार-दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग और ऐता गांव

दुगड्डा ब्लॉक के भवासी गांव में पहुंचा हाथी

तक हाथियों की आवाजाही आम रही है। लेकिन इस बार हाथी दुगड्डा से आगे बढ़कर भंवासी क्षेत्र तक पहुंच गया, जो वन विभाग और स्थानीय लोगों दोनों के लिए चिंता का विषय है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव एवं वरिष्ठ वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ. दिनेश चंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले दो दिनों से जयगांव, भटगांव बागी और भंवासी क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक वयस्क हाथी को विचरण करते देखा है। उनके अनुसार, हाथी हिंवल नदी के किनारे वाले क्षेत्र में देखा गया है। हिंवल नदी आगे गरुड़ चट्टी के समीप गंगा में मिलती है। संभावना है कि यह हाथी हरिद्वार वन प्रभाग अथवा राजाजी क्षेत्र से भटककर यहां पहुंचा हो। डॉ. भट्ट ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही बाघ, गुलदार, भालू, जंगली सूअर और बंदरों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में हाथी की आमद से फसलों को नुकसान और मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरे पुत्र का नाम RUDHRANSH RAWAT अंकित है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम ATHARV RAWAT है। अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका सही व वास्तविक नाम ATHARV RAWAT अंकित कर संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

सावन सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी पटखोली, काण्डाखाल, कौड़िया, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(0552/21)

पुरानी पेंशन बहाली और टीईटी से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

जयन्त प्रतिनिधि।

थलीसैंण : प्रदेश कार्यकारिणी उत्तराखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ के आवाह्न पर ब्लॉक कार्यकारिणी थलीसैंण ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली और अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि मांगें नहीं माने जाने पर संघ की ओर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए।

इस अवसर पर शिक्षकों ने सरकार द्वारा शिक्षकों पर एनपीएस और टीईटी जबरन थोपने का घोर विरोध और निंदा की। कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का आत्म सम्मान है, जिसे हम हर हाल में हासिल करके रहेंगे। उन्होंने समस्त शिक्षक और कर्मचारियों से जिला और प्रदेश स्तर के आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड को उपजिलाधिकारी थलीसैंण के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली और अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा गया। इस मौके पर ब्लॉक कार्यकारिणी अध्यक्ष आनन्द प्रसाद ममगांई, दीप धस्माना, नरेश रावत, सुरेश राही, कन्हैया लाल, संतोष ममगांई, शीतल रावत, अभिनव वत्सल, आनन्द रावत, कन्हैया नौटियाल, दयाराम चौहान, प्रदीप धस्माना, विनोद चौहान, शीतल रावत, सुभाष, विमलेश भट्ट, हरीश चन्द्र, चन्दन लाल, राकेश सिंह, भूपेन्द्र सिंह, ईशा धूलिया, रेनू बिष्ट, रश्मि पाल, वीर सिंह, प्रखर सिंह, वृजेश आदि मौजूद थे।

भारतीय परंपरा में ज्योतिष और आयुर्वेद का विशेष महत्व

श्रीनगर गढ़वाल : वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान में हिमालय ज्योतिष संरक्षण एवं विकास परिषद की ओर से चिकित्सा ज्योतिष विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष के पारंपरिक संबंधों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। कहा गया कि भारतीय परंपरा में ज्योतिष और आयुर्वेद का विशेष महत्व रहा है। प्रो. रामानंद गैरोला ने राशियों के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों की व्याख्या करते हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पारंपरिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। परिषद के अध्यक्ष आचार्य भाष्करानन्द अणथ्वाल ने कहा कि चिकित्सा ज्योतिष को आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। चिकित्सकीय परामर्श के साथ योग, ध्यान और अन्य पारंपरिक उपाय रोगियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। संचालन डॉ. दीपक द्विवेदी ने किया।

अदालती सूचना

न्यायालय श्रीमान असिस्टेंट कलेक्टर महोदय लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल।
बंटवारा वाद संख्या 10 /2024-25
वादी- राजवर सिंह
बनाम
प्रतिवादीगण - अर्जुन सिंह आदि
नोटिस बनाम - आम व खास
1- लक्ष्मण सिंह पुत्र चन्दन सिंह, 2- भारत सिंह पुत्र चन्दन सिंह, 3- पूर्ण सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, 4- मुन्नी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह, 5- पार्वती देवी पत्नी आनन्द सिंह, 6- विनोद सिंह, 7- मनोज सिंह पुत्रगण आनन्द सिंह, 8- रेखा देवी पत्नी चन्द्रपाल सिंह, 9- सोबन सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह, 10- नितिन सिंह पुत्र जगत सिंह, 11- लता देवी पत्नी जगत सिंह, 12- राजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह, 13- रोहित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, 14- ललिता देवी पत्नी अर्जुन सिंह निवासी ग्राम गौलीखेत, पट्टी त0 बदलपुर, तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

हरगाह वादी ने आपके खिलाफ एक बंटवारा दावा बावत खाता सं0 0005 ग्राम गौलीखेत, पट्टी त0 बदलपुर, तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें वास्ते जवाबदावा दिनांक 30/07/2026 नियत है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि वादी के वाद पर कोई उज्र एतराज हो तो उक्त नियत तिथि को प्रातः 10 बजे न्यायालय लैन्सडौन में स्वयं य जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा मामले में वादी के हक में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आज दिनांक 08/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर द्वारा जारी किया गया।

न्यायालय असिस्टेंट कलैक्टर (प्र0श्रे0)
लैन्सडौन, गढ़वाल
(0553/15)

पोखरी में बहुउद्देशीय सेवा एवं जनकल्याण शिविर आयोजित, 215 लोगों ने उठाया लाभ

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : सेवा, सुशासन एवं समर्पण सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को विकासखंड सभागार पोखरी में बहुउद्देशीय सेवा एवं जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।

शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे बहुउद्देशीय

शिविरों के माध्यम से लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी लोगों को अवगत कराया। शिविर में कुल 215 लोगों ने प्रतिभाग किया, जबकि 128 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कृषि विभाग ने 9 किसानों को कृषि बीज वितरित किए। उद्यान विभाग ने 9 लाभार्थियों को सब्जी बीज किट उपलब्ध कराई। समाज कल्याण विभाग ने 18 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। उद्योग विभाग ने 5 लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया।

संपादकीय

सौहार्द पर खतरा "बयानवीर"

राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए जनता को किस प्रकार से उत्तेजित करना है यह राजनेता बखूबी जानते हैं। आय दिन ऐसे बयान विभिन्न धमी के नेताओं या फिर धार्मिक गुरुओं द्वारा दिए जाते हैं जिनके पीछे केवल वैमनस्य एवं सांप्रदायिकता फैलाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। खास तौर से राजनीतिक मंच से ऐसे बयानों की धारा प्रवाह नदिया बहती है। इनमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से लेकर धार्मिक सामाजिक और जातीय शब्दों का प्रयोग आम बात हो गई है। माना कि लोकतांत्रिक समाज में विचारों की अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जब यह अभिव्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने, समाज को बांटने या किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाने का माध्यम बन जाए, तब यह अधिकार नही बल्कि सामाजिक संकट का कारण बन जाती है। गैर–जिम्मेदाराना और भड़काऊबयानों ने इस चिंता को और गहरा किया है। जब कोई व्यक्ति, संगठन या प्रभावशाली मंच धार्मिक विषयों पर तथ्यहीन, उत्तेजक या अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो इसका असर केवल शब्दों तक सीमित नही रहता। ऐसे बयान लोगों के मन में अविश्वास, कटुता और विभाजन की भावना को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और गंभीर हो गई है। पहले कोई विवादित बयान सीमित दायरे में रहता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार अपुष्ट सूचनाएं, पुराने वीडियो या भ्रामक संदेश धार्मिक रंग देकर प्रसारित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप लोग तथ्यों की बजाय भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं और समाज में तनाव का वातावरण बन जाता है। ऐसी बयान वीरता क्षणिक लोकप्रियता तो दे सकती है लेकिन दीर्घकाल में सामाजिक व्यवस्था कमजोर करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब समाज संवाद की जगह उकसावे को महत्व देने लगता है, तब शांति और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। यहां चिंता की बात यह है कि मीडिया आपकीजिम्मेदारियां का सही तरीके से पालन नही करता। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को यह समझना होगा कि उनके शब्द केवल व्यक्तिगत विचार नही होते, बल्कि वे लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए संयमित भाषा, तथ्य आधारित चर्चा और परस्पर सम्मान की भावना को प्राथमिकता देना समय की मांग है। वे राजनीति के लिए ऐसा करते हैं लेकिन आम नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। किसी भी धार्मिक संदेश, वीडियो या पोस्ट को बिना सत्यापन के साझा करना ठीक नही। आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक मतभेदों को संवाद और समझ के माध्यम से सुलझाया जाए, न कि उत्तेजक बयानों और आरोप–प्रत्यारोप के जरिए। समाज को जोड़ने वाले शब्द हमेशा समाज को तोड़ने वाले शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम बयान देने वाले के मंसूबे को समझें।

विकसित भारत की राह में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न

ललित गर्ग

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- 'युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए।' यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है।

भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अतः सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से बढ़कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो विकसित भारत का लक्ष्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जनगणना और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस नीति में संशोधन भी किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, इसलिए यहां समाधान कठोर दमनात्मक उपायों के बजाय समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, परिवार नियोजन, जन-जागरूकता और कानून के निष्पक्ष अनुपालन में निहित है। जनसंख्या के प्रश्न को जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के हित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम भी इसी दिशा में संकेत करती है कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिलेंगे, तो वे स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनकर संतुलित परिवार और सतत विकास की दिशा में योगदान देंगे। भारत की लगभग आधी आबादी युवा है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश तभी राष्ट्र की शक्ति बनेगा, जब यह शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। अन्यथा यही विशाल युवा आबादी बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक व्यापक, वैज्ञानिक और सर्वसम्मत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसी नीति में समानता, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी किसी भी चर्चा में सामाजिक सौहार्द, तथ्यपरक विश्लेषण और जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या विभाजनकारी दृष्टिकोण समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे सकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, मानव पूंजी में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, प्रभावी सीमा प्रबंधन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति-इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। यदि भारत समय रहते जनसंख्या संतुलन, मानव विकास और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का लक्ष्य अधिक यथार्थ रूप में साकार हो सकेगा।

समान नागरिक संहिता: कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात?

दिलीप कुमार पाठक

भारत की राजनीति में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है, जो जब भी सामने आता है, अपने साथ बहसों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इसे लागू किए जाने के बाद, अब देश के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्रों में ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया जाए। लेकिन क्या देश के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में से एक में इसे लागू करना इतना सीधा रास्ता है? या फिर इस कदम की टाइमिंग के पीछे चुनावी समीकरणों की कोई गहरी बिसात बिछी है?

जब हम सरकार के इस फैसले को बारीकी से देखते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को निष्पक्षता से तौलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज नीति निदेशक तत्वों के तहत एक राष्ट्र, एक कानून के सपने को सच करने की दिशा में एक साहसिक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा और सदियों पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। इस समिति की कमान जस्टिस रंजना देसाई को सौंपना प्रशासनिक रूप से एक सोची-समझी रणनीति दिखती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले उत्तराखंड के कानून का मसौदा तैयार किया था। उनके इस तकनीकी अनुभव का लाभ महाराष्ट्र सरकार उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में शाह बानो और सरला मुद्गल जैसे ऐतिहासिक मामलों में देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया है, जिससे इस विचार को संवैधानिक मजबूती मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर और वास्तविक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसी सीमित आबादी वाले राज्य और महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं, प्रथाएं और सामाजिक नियम हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल अल्पसंख्यक समुदाय और अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों का एक बेहद पेचीदा ताना-बाना है। इतने बड़े और विविधता से भरे राज्य में बिना किसी व्यापक सामाजिक संवाद के, केवल छह महीने के भीतर एकतरफा मसौदा तैयार कर लेना जमीनी सच्चाइयों से आंखें मूंदने जैसा हो सकता है।

भारत का संविधान जहां एक तरफ समानता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी कानूनविद के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। एक और बड़ा सवाल इस समिति की बनावट पर भी उठ रहा है। सात सदस्यों की इस समिति में पूर्व जजों, पूर्व मुख्य सचिव और संवैधानिक विशेषज्ञों को तो जगह मिली है, लेकिन अल्पसंख्यक या आदिवासी समुदायों के जमीनी प्रतिनिधियों की कमी साफ खलती है। जब आप समाज के हर वर्ग के निजी जीवन को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा कानून बनाने जा रहे हों, तो उस चर्चा की मेज पर सभी पक्षों की मौजूदगी न होना कानून की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के हर तबके को अपना सा लगे, न कि किसी पर थोपा हुआ महसूस हो। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की टाइमिंग पर भी लगातार उंगली उठा रहे हैं। यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश या राज्य में जब भी कोई बड़ा चुनाव नजदीक आता है या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले होते हैं, तभी समान नागरिक संहिता जैसे भावनात्मक मुद्दों को तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जाता है? अगर मंशा सचमुच केवल कानूनी और सामाजिक सुधार की है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जन-सुनवाई क्यों नहीं की जाती? सभी हितधारकों, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकताओं से खुलकर चर्चा करने में आखिर क्या हिचक है? समान नागरिक संहिता अपने आप में एक प्रगतिशील और आधुनिक विचार हो सकती है, बशर्ते उसे सुधार की सच्ची नीयत से लाया जाए, न कि किसी राजनीतिक लाभ या ध्रुवीकरण के लिए। भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में कोई भी नागरिक कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। यदि महाराष्ट्र सरकार वाकई इस दिशा में कोई सार्थक और ऐतिहासिक बदलाव करना चाहती है, तो उसे जल्दबाजी छोड़कर इस कानून को सर्वसम्मति, पारदर्शिता और बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा, यह कदम भी एक वास्तविक सामाजिक सुधार बनने के बजाय केवल एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा। (लेखक पत्रकार हैं)

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंका

नीरज कुमार दुबे

नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा।

हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा

अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है।

देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित अन्य गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

साथ ही मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साइबर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तुत यह नई रणनीति केवल सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सामरिक शक्ति और भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने वाला व्यापक अभियान बनकर उभर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह स्वयं भी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों के साथ संवाद स्थापित किया, नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया, भारत-पाक सीमा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र जाकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और महिला जवानों के लिए नई बैरकों का उद्घाटन किया। स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र, मजबूत समन्वय और प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे सीमा सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान ने माना, बलूचिस्तान में 38 सुरक्षा कर्मी मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। बलूचिस्तान में पिछले चार दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सेना और पुलिस के 38 जवानों को मार गिराया। खुद पाकिस्तानी सेना की इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जियो टीवी के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली घटना 4 और 5 जुलाई की रात को हन्ना उराक में हुई थी। यहां मांगी डैम पर पहले दिन नौ पुलिसकर्मी मारे गए और बाद में 18 और मारे गए, जिससे कुल संख्या 27 हो गई। तीसरी घटना डेला बंदर में बुधवार को सेना के काफिले से जुड़े एक ऑपरेशन के दौरान हुई। काफिले और बीएलए सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई। काफिले पर हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर समेत 11 जवान मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जियारत जिले में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है।

बांग्लादेश में लैंडस्लाइड से 8 बच्चों की मौत, 5 घायल; लगातार बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ा

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के उखिया स्थित रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में बुधवार को लैंडस्लाइड में 8 बच्चों की मौत हो गई और 5 घायल हैं। सभी बच्चों की उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। बांग्लादेश मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। लगातार हो रही भारी बारिश और भारत से आने वाले ऊपरी इलाकों के पानी की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिपैट्रिएशन कमिश्नरके बयान के अनुसार, घटनास्थल से 13 बच्चों को बाहर निकाला गया। इनमें से चार बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार ने अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी पांच बच्चों का अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज चल रहा है। इसी बीच, अंधेरा होने के बाद फायर सर्विस ने बचाव अभियान रोक दिया।

ऑस्ट्रेलिया में टेल्सट्रा का नेटवर्क ठप: 12 घंटे तक मोबाइल सेवाएं बाधित, ट्रेनें रुकीं

केनबरा, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेल्सट्रा के नेटवर्क में बुधवार तड़के आई तकनीकी खराबी से देशभर में मोबाइल कॉल और डेटा सेवाएं करीब 12 घंटे तक प्रभावित रहीं। इसका असर ट्रेन सेवाओं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और इमरजेंसी कॉल पर भी पड़ा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह साइबर अटैक नहीं बल्कि सिडनी और मेलबर्न के डेटा सेंटर में टाइम-कीपिंग सर्वर से जुड़े सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण हुआ। आउटेज के दौरान कुछ इमरजेंसी कॉल कनेक्ट नहीं हो सकीं। कंपनी ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की और प्रभावित लोगों का वेलफेयर चेक कराया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को 'बेहद चिंताजनक' बताया। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशंस एंड मीडिया अथॉरिटी पूरे मामले की जांच करेगी। नेटवर्क बाधित होने से विक्टोरिया में सभी क्षेत्रीय ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ीं, जबकि न्यू साउथ वेल्स में भी कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। फ्रेट सर्विसेस भी प्रभवित रहीं।

मरीन ले पेन को राहत: अपील कोर्ट ने चुनावी प्रतिबंध घटाया; 2027 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगी

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस की अपीलीय अदालत ने दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को यूरोपीय संसद फंड के दुरुपयोग मामले में दोषी तो माना, लेकिन उन पर सार्वजनिक पद संभालने की पाबंदी कम कर दी। इसके बाद ले पेन ने घोषणा की है कि वह 2027 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी। पेरिस कोर्ट ऑफ अपील ने ले पेन पर लगाए गए पांच साल के चुनावी प्रतिबंध को घटाकर 45 महीने कर दिया, जिनमें से 30 महीने निलंबित रहेंगे। अदालत ने यह भी माना कि 31 मार्च 2025 से वह पहले ही प्रतिबंध की अवधि पूरी कर रही हैं। इस वजह से वह 2027 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो गई हैं। अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा भी सुनाई है। इसमें दो साल की सजा निलंबित है, जबकि एक साल इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ नजरबंदी में बिताना होगा।

ईरान का खौफ: ट्रंप ने बीच रास्ते में बदला विमान, कतर का जेट छोड़ पुराने 'एयरफोर्स वन' में बैठे

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौटते समय ट्रंप ने कतर द्वारा गिफ्ट में दिए गए नए बोइंग 747-8 जेट की बजाय अपने पुराने 'एयरफोर्स वन' से उड़ान भरी। ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में एक छोटे से ठहराव के बाद विमान बदलने के इस फैसले ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया गया फैसला : द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद, यूएस सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप को विमान बदलने की सलाह दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसी विशेष खतरे की प्रतिक्रिया के बजाय केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया था। दरअसल, कतर की ओर से मिले नए विमान में अभी तक वे सभी एडवांस सुरक्षा फीचर्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जो मौजूदा 'एयरफोर्स वन' के बेड़े में मौजूद होते हैं।

हालांकि, वाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है कि नया विमान असुरक्षित है। वाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने स्पष्ट किया कि नया जेट 'उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल' से लैस है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राष्ट्रपति की सुरक्षा के

लिए 'ध्यान भटकाने और गुमराह करने' समेत अपने हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करता है।

ट्रंप बोले- 'मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर वन हूं' : विमान बदलने के पीछे सुरक्षा चिंताओं की बात को खुद ट्रंप ने भी खारिज कर दिया। ब्रिटेन से रवाना होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन हूं। ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में रुकने का असली मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैन्यकर्मियों को नया विमान दिखाना था। उन्होंने नए विमान को 'बिल्कुल नया और शानदार' बताते हुए सैन्यकर्मियों के साथ इसकी तस्वीरें भी साझा कीं और कहा कि वे लोग इसे देखकर काफी उत्साहित थे। पुरानी 'एयरफोर्स वन' से सफर करने के पीछे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 'पुरानी यादों को ताजा करने के लिए' ऐसा किया है।

खिड़कियों के ब्लाइंड्स बंद रखने का था निर्देश : इस यात्रा के दौरान पुरानी एयरफोर्स वन में सफर कर रहे पत्रकारों को फ्लाइट में खिड़कियों के ब्लाइंड्स (पर्दे) बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने बताया कि यह पाबंदी उनके निजी कंपार्टमेंट पर लागू नहीं थी। उन्होंने ईरान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा यहां मौजूद 'स्लीजबैग्स' की वजह से किया गया हो। विमान बदलने का यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका ने तेहरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ईरानी ठिकानों पर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बहरीन, कुवैत और कतर में मिसाइल हमले के चेतावनी सायरन बजने लगे। वहीं, कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने अपनी तरफ आ रही मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया है।

न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, ईरान से 'हॉर्मुज' पर नहीं हो पाई डील: जेडी वेंस

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। पहले ईरान ने होर्मुज में जहाजों पर हमला किया और उसके बाद अब अमेरिका ने पलटवार किया। ईरान के बंदरगाहों पर हवाई हमले किए। इस बीच, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया है कि ईरान से शांति वार्ता की कोशिशों के बीच गोलीबारी कैसे शुरू हो गई और किस वजह से शांति को लेकर समझौता नहीं हो पाया। जेडी वेंस के मुताबिक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। उनकी पारंपरिक सेना को भी खत्म कर दिया गया है। हमारी डील की मुख्य बात यह थी कि अगर आप जहाजों पर गोलाबारी को रोक देंगे, तो हम अपनी नाकेबंदी को हटा लेंगे। लेकिन अगर आप जहाजों पर बम-गोले दागेंगे, तो हम पलटवार करेंगे और पहले से कहीं ज्यादा जोरदार पलटवार करेंगे। डील यही थी। लेकिन 24 घंटे पहले क्या हुआ? ईरान ने फिर से जहाजों पर गोलाबारी शुरू कर दी। हमारी डील बहुत सीधी-सादी है लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आगे कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बहुत साफ शब्दों में कहा कि Strait of Hormuz खुला रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी लोगों तक तेल और गैस की सप्लाई होती रहेगी। ट्रंप ने कहा कि वह अहम रास्ता जिससे विश्व की बहुत सारी ऊर्जा की सप्लाई होती है।

ट्रंप से रिश्ते सुधारने की कोशिशों पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोलीं- कोई पछतावा नहीं

रोम, एजेंसी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिशों पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों नेताओं के बीच ईरान मुद्दे पर सार्वजनिक बहस, निजी टिप्पणियां और सोशल मीडिया पर नोकझोंक चल रही है। इसके बावजूद मेलोनी अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं।

बुधवार को अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद मेलोनी ने ट्रंप के साथ संबंध बनाने के अपने प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण हमेशा इटली के राष्ट्रीय हितों और पश्चिमी देशों की एकता पर आधारित रहा है, न कि व्यक्तिगत राजनीति पर। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश पर पछतावा है, तो उन्होंने थोड़ा रुककर पानी पिया और दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की एकता में विश्वास के कारण उन्होंने यह राजनीतिक निवेश किया था। यह कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो उन्होंने केवल ट्रंप के आने पर अपनाई हो, बल्कि वह सभी नेताओं के साथ ऐसा ही करती हैं। कभी मेलोनी को यूरोप में ट्रंप का सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी माना जाता था। वह ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय शासनाध्यक्ष थीं।

उन्हें वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं। दरार तब शुरू हुई जब मेलोनी ने पोप लियो पर ट्रंप के हमलों की आलोचना की। पोप ने ईरान युद्ध की निंदा की थी। इसके बाद इटली ने पश्चिम एशिया जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली के सिगोनेला हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे रिश्ते और बिगड़ गए। ट्रंप ने ईरान पर इटली के रुख की आलोचना की और अमेरिका का समर्थन न करने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने मेलोनी को एक अच्छी इंसान भी बताया। विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने दावा किया कि फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनसे तस्वीर खिंचवाने की भीख मांगी थी।

ईरान ने किया बहरीन और कुवैत में हमले का दावा, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की भी बात कही

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका द्वारा ईरान के दक्षिणी प्रांतों में किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बुशेहर प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी रूक्-9 ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी सेना के बयान में कहा गया, 'अमेरिकी दुश्मन द्वारा देश के दक्षिणी क्षेत्रों पर किए गए हमले के बाद हमारी सेना के ड्रोन ने बहरीन स्थित शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी बलों के ठिकानों पर हमला किया।' इससे पहले ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने नौसेना और एयरोस्पेस बलों के संयुक्त अभियान में बहरीन और कुवैत में 85 महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहरीन के सलमान पोर्ट, वहां तैनात अमेरिकी पांचवें बेड़े के ठिकानों और कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना की ओर से बुधवार तड़के किए गए।

पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा बलूचिस्तान तट के पास मिला

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात कराची पहुंचने से पहले लापता हो गया था। विमान शारजाह से कराची आ रहा था और उसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तानी खोजी दलों ने बलूचिस्तान के तट के पास अरब सागर में ओर्मारा से 53 समुद्री मील (लगभग 98 किलोमीटर) दूर विमान का मलबा बरामद कर लिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, रात 9:18 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी। कंट्रोल रूम ने विमान को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन करीब तीन मिनट बाद उसका संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान कराची से 155 नॉटिकल मील (287 किमी) पश्चिम में ट्रैक किया गया। विमान के लापता होने के बाद अरब सागर में बड़े स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और अन्य एजेंसियां खोज अभियान में जुटी रही।

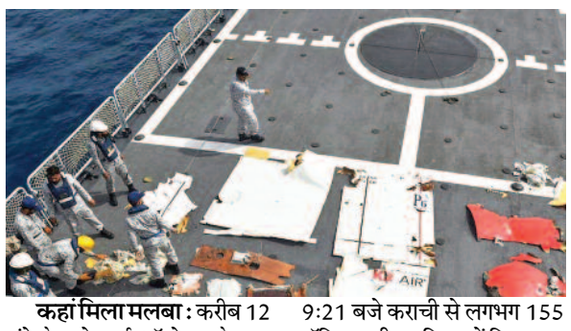

कहां मिला मलबा : करीब 12 घंटे के बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद ओर्मारा बंदरगाह से 53 नॉटिकल मील दक्षिण में विमान का मलबा बरामद किया गया। विमान ने मंगलवार शाम शारजाह से उड़ान भरी थी। संपर्क टूटने से ठीक पहले विमान की ओर से नेविगेशन सिस्टम में खराबी की रिपोर्ट दी गई थी।

कैसे हुआ हादसा : पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, रडार डेटा से पता चला है कि विमान ने अचानक अपनी दिशा में बड़ा बदलाव किया और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात करीब 9:21 बजे कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील पश्चिम में विमान का रेडियो और रडार से संपर्क पूरी तरह टूट गया था।

रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन-कौन शामिल : हादसे का अलर्ट मिलते ही बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अरब सागर में चलाए जा रहे इस अभियान में पाकिस्तान नेवी के युद्धपोत 'पीएनएस जुल्फिकार', नेवल सर्विलांस एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों के साथ-साथ मर्चेंट जहाजों को भी तैनात किया गया है।

ये 5 क्रू मेंबर हैं लापता : के2 एयरवेज ने बयान जारी कर बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वे पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लापता क्रू मेंबर्स के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए हर संभव संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए।

हादसे की वजह पर एक्सपर्ट्स की राय : हालांकि विमान के गायब होने से पहले नेविगेशन सिस्टम में खराबी की बात सामने आई थी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर एआरवाई न्यूज से बातचीत में एविएशन एनालिस्ट इमरान असलम ने बताया कि अगर विमान का इंजन फेल भी हो जाए।

भारतीय इंजीनियर ने अमेरिका में की पत्नी की हत्या

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रह रहे एक 30 वर्षीय भारतीय इंजीनियर को यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंजीनियर पर नौ माह पहले अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि भारतीय इंजीनियर अविनाश नारने ने अपनी पत्नी रंजीता सब्बीनेनी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के शव की फोटो भारत में रह रही अपनी प्रेमिका को भी भेजी थी। पुलिस जांच के बाद हत्या का मामला साफ हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे रची भारतीय इंजीनियर ने साजिश : 27 अक्टूबर, 2025 को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारने ने पुलिस को फोन करके बताया कि उनकी पत्नी बाथरूम में बंद हैं और बाहर नहीं आ रही हैं। जब पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें सबिनेनी जमीन पर पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के दौरान, नारने ने पुलिस को बताया कि वह कुछ काम से अपार्टमेंट से बाहर गए थे। जब वह लगभग 40 मिनट बाद घर लौटे, तो उन्होंने सबिनेनी को बाथरूम में बंद पाया। हालांकि, अधिकारियों को नारने के बाहर रहने के दौरान घर में किसी और के घुसने का कोई सबूत नहीं मिला।

भारत में रहने वाली लड़की से थे प्रेम संबंध : अगले दिन, किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस ने सबिनेनी की मौत को हत्या करार दिया और कहा कि उनकी मौत गला घोंटे जाने के कारण दम घुटने से हुई थी। जांच से पता चला कि नारने का भारत में एक महिला के साथ कई वर्षों से रिश्ता था। उस महिला के साथ रिश्ते में रहते हुए ही, नारने की 5 जून, 2025 को सबिनेनी से शादी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि नारने की गर्लफ्रेंड भी उनकी शादी में शामिल हुई थी। हालांकि, सबिनेनी से शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता चलता रहा।

प्रेमिका को पत्नी के शव की तस्वीर भेजी : घटना वाले दिन, नारने ने अपनी गर्लफ्रेंड को कम से कम चार बार फोन किया था, जिसमें वह समय भी शामिल था जब उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह बंद बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि नारने ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी की लाश की तस्वीर भी भेजी थी। अधिकारियों को जांच में सबिनेनी के नारने को भेजे गए टेक्स्ट मैसेज भी मिले, जिनमें सब्बीनेनी ने कई बार शिकायत की थी कि नारने जो ड्रिंक्स उनके लिए बनाते थे, उनका स्वाद कड़वा होता था। अपनी मौत के दिन, उन्होंने अपने पति को मैसेज किया था कि उनके बनाए स्मूदी का स्वाद दवा और कफ सिरप जैसा था। 5 जुलाई को नारने पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है।

डीआर कांगो में इबोला वायरस का कहर जारी, 600 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा

किंशासा , एजेंसी। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इससे मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई है और 1,759 मामलों की पुष्टि हुई है। बुधवार देर रात जारी एक अपडेट में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अभी कुल 750 मरीज आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पतालों में 94 प्रतिशत बेड भरे हुए हैं। बुंडीबुग्यो इबोला वायरस से होने वाला यह प्रकोप, जिसे 15 मई को घोषित किया गया था, देश का 17वां इबोला प्रकोप है। इसने तीन प्रांतों - इतुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु - के 37 स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकोप से निपटने में कई बाधाएं आ रही हैं, जिनमें पोस्टमार्टम के लिए सैंपल लेने का समुदाय द्वारा विरोध, इलाज की अपर्याप्त क्षमता, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, सीमित सप्लाई, असुरक्षा और हथियारबंद समूहों से प्रभावित इलाकों तक सीमित पहुंच शामिल हैं। डीआरसी ने मई के मध्य में इस प्रकोप की घोषणा की थी। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि असुरक्षा, लोगों की आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और अधूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण स्थिति से निपटना मुश्किल हो रहा है। इबोला वायरस से होने वाली एक दुर्लभ, गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी है।

यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फ्रूट बैट) से इंसानों में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों (बॉडी फ्लूइड्स) के सीधे संपर्क से फैलता है। इसमें अचानक फ्लू जैसे लक्षण और बुखार आता है। इससे शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। मई 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप की पुष्टि हुई थी। इसमें शामिल इबोला की बुंडीबुग्यो प्रजाति के लिए कोई वैक्सीन या खास इलाज नहीं है, हालांकि संभावित वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह प्रकोप एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हो रहा है: मानवीय संकट, दूरस्थ और घनी आबादी वाला क्षेत्र, साथ ही असुरक्षा और भारी जनसंख्या एवं व्यापारिक आवागमन। इसके लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। इनमें अचानक बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, तेज़ सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गंभीर मामलों में बिना किसी स्पष्ट कारण के ब्लीडिंग या शरीर पर निशान पड़ना शामिल है।

अब यूक्रेन खुद बनाएगा पैट्रियट एयर डिफेंस, रूस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक कूटनीति और युद्ध के मैदान की समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में आयोजित ह्वाइट हाउस शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा 'रक्षा तोहफा' दिया है।

यूक्रेन को मिला 'सुरक्षा कवच' का लाइसेंस : तुर्की में दुनिया के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का आधिकारिक लाइसेंस देगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि यूक्रेन न केवल अमेरिकी मदद पर निर्भर रहे, बल्कि अपनी धरती पर खुद इन मिसाइलों का निर्माण कर रूसी मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जेलेंस्की पिछले काफी समय से अमेरिका से इस तकनीक और लाइसेंस की मांग कर रहे थे, जिसे अब ट्रंप प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है।

क्यों 'जैकपॉट' है पैट्रियट सिस्टम : पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे घातक जमीन से हवा में मार करने वाली तकनीक माना जाता है। अमेरिकी दिग्गज कंपनियों लॉकहीड मार्टिन

और रेथियॉन द्वारा विकसित यह सिस्टम किसी भी आधुनिक हमले को नाकाम करने में सक्षम है। इसकी विशेषताएं इसे बेहद खास बनाती हैं: घातक मिसाइलें: पूरे सिस्टम में एक रडार सेट, एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर और घातक मिसाइलें शामिल होती हैं। वर्तमान में दुनिया के केवल 13 चुनिंदा देशों के पास ही यह तकनीक उपलब्ध है और अब यूक्रेन इस सूची में अपना नाम मजबूती से दर्ज करा रहा है।

'शांति की ओर एक बड़ा कदम' : इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ हुई बैठक को बेहद सकारात्मक बताया। जेलेंस्की ने कहा कि वे लोगों की जान बचाने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने के अमेरिकी फैसले के लिए आभारी हैं। उन्होंने जोर दिया कि इस बातचीत से यूक्रेन की स्थिति न केवल युद्ध के मैदान में मजबूत होगी, बल्कि यह कूटनीति और शांति की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

युद्ध की दिशा पर प्रभाव : यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का लाइसेंस मिलना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब तक यूक्रेन को इन मिसाइलों के लिए अमेरिका की सप्लाई चेन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह कदम स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में रूस-यूक्रेन संघर्ष एक नए और अधिक तकनीकी मोड़ पर पहुंचने वाला है।

तब बाढ़ में भी नहीं डूबेंगे धान के पौधे!

तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। अब जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीनों का पता लगाया है जिनके जरिए चावल के पौधे का विकास इस तेजी से बढ़ाया जा सकता है कि वह पानी में डूबे ही नहीं।

भारत में चावल उगाने वाले किसान जहां बरसात के लिए तरसते हैं, वहीं उससे बहुत डरते भी हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं, क्या बरसात ठीक वक्त पर आएगी, ज़्यादा तेज और लंबी तो नहीं होगी, कितनी बार फसल बरसात की वजह से खराब हो जाती है और हज़ारों किसानों के लिए भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों में भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।

अक्सर यह देखा गया है कि तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। खेतों मे बढ़ता हुआ जलस्तर चावल के पौधों के लिए सामान?यत- अच्छा ही रहता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि पौधे के उपरी हिस्से हवा के संपर्क में बने रहें। हालांकि मानसूनी इलाकों में बरसात और बाढ की वजह से चावल के खेतों में पानी इतना ज?यादा भर जाता है कि धान के पौधे बिल्कुल डूब जाते हैं तथा इससे वे सड़ने लगते हैं और मर भी जाते हैं।

गौरतलब है कि गहरे पानी में उगनेवाले चावल की प्रजाति को जलजमाव से कोई समस्या नहीं होती। पानी के साथ-साथ उसके तने वाले डंठल भी बढ़ते जाते हैं।

जापान के नागोया विश्वविद्यालय के मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

गहरे पानी में उगने वाले चावल के पौधे, पानी की गहराई से ऊपर बने रहने के लिए, एक मीटर तक बढ़ सकते हैं। वे हवा के संपर्क में बने रहने के लिए ऐसा करते है। वे अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन उसके जरिए पौधा पानी की सतह से उपर पहुंच सकता है और ऑक्सीजन पा सकता है। यह कुछ ऐसा ही है कि जब आप गोताखोरी कर रहे होते हैं, तो पानी से ऊपर निकली एक नली से सांस लेते हैं।

बरसात के समय ऐसे चावल के तने 25 सेंटीमीटर प्रतिदिन की एक अनोखी गति से बढ़ सकते हैं। अशिकारी और उनकी टीम ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस चावल के जीनों से यह समझने की कोशिश की कि चावल बरसात के वक्त अपने विकास को किस तरह नियंत्रित करता है। अध्ययनों से अब तक जितना पता चला है वह यह है कि एक गैसीय विकास-हॉर्मोन एथीलिन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसाकि नीदरलैंड के उएतरेश्त विश्वविद्यालय के रेंस वोएसेनेक बताते हैं-

जब पौधा पूरी तरह पानी में डूब जाता है तब यह गैस ठीक तरह से मुक्त नहीं हो पाती। यू कहें कि वह पौधे में ही कैद हो जाती है। यानी पौधे में एथिलिन की मत्रा बढ़ने लगती है। यह पौधे के लिए संकेत है कि वह पानी में डूब रहा है और उसे कुछ करना है।

जापानी विशेषज्ञों ने पता लगाने की कोशिश की कि कौन से जीन इस स्थिति में सक्रिय होते हैं। उन्होने ऐसे जीन पाए जिनको वे गोताखोरी में इस्तेमाल होनेवाली नली के अनुरूप स्नोर्कल जीन कहते हैं। ये जीन तभी सक्रिय होते हैं जब पौधे के तने में एथिलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। वे पौधे के विकास को तेज करने वाले दूसरे तत्वों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

हमने क्रॉमोसोम 1,3 और 12 पर यह तथाकथित नलिका जीन पाए। उन्हें यदि सामान्य चावल के पौधों में भी मिलाया जा सके, तो बरसात के वक्त सामान्य चावल के पौधे भी वही करेंगे जो गहरे पानी में उगने वाला चावल करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चावल की हर प्रजाति को गहरे पानी में उगने वाले चावल की प्रजाति बना सकते हैं।

यानी इन जीनों की मदद से चावल की उस फसल को बचाया जा सकता है जो पानी की अधिकता के प्रति बहुत संवेदनशील है। जहां अक्सर बाढ आती है वहां के किसानों की इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक और समस्या भी दूर हो सकती है - गहरे पानी में उगने वाला चावल बहुत ही कम फसल देता है, प्रति हेक्टेयर सिर्फ एक टन जो उपजाऊ क़िस्मों की तुलना में सिर्फ 20 फीसदी के बराबर है। नीदरलैंड के विशेषज्ञ रेंस वोएसेनेक बहुत ही आशावादी हैं-

विकास के लिए जिम्मेदार इन जीनों के बारे में पता चल जाने के बाद अब हम चावल की अलग-अलग प्रजातियों के बीच प्रकृतिक संवर्धन के जरिए, यानी वर्णसंकर के जरिए भी इन जीनों को उनके पौधे में डाल सकते हैं। इसके लिए किसी जीन तकनीक जरूरत ही नहीं हैं।

जापान के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर भी दिया है। उनके अध्ययनों से एक बार फिर पता चलता है कि पौधों के संवर्धन के लिए उनके जीनों में असामान्य गुणों की तालाश कितनी जरूरी है।

कुदरती खेती का एक अनूठा प्रयोग

भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रकृति की कृपा तथा हमारे किसानों कि आर्थिक मेहनत से हमारी भूमि सदा उपजाऊ रही है। प्राचीन समय में हमारी खेती प्राकृतिक संपदा व संसाधनों पर ही निर्भर थी और देश की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर पाती थी। जैसे-जैसे देश में शहरीकरण व औद्योगिकरण बढते गये , गांवों से लोग खेती को छोड़ शहरों की ओर आते गये। प्राकृतिक खेती पध्दति कम होती गई और रासायनिक खाद आदि का प्रयोग बढता गया। ज़मीन की उत्पादकता घटती गई और साथ ही किसान की आय भी। सन 1965 में भारत में हरित क्रांति आयी जिससे उपज तो बढी मगर रासायनिक उरवरक तथा अन्य उत्पादों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से मिटटी की उत्पादकता भी कम होती गयी।

यूरोप, अमरीका व एशिया में सन् 1940-50 के दकों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं पर बहुत प्रयोग किये गये। खेती कि ये विधायें भारत में सन 1980 के दशक से आगे बढी हैं। जैविक खेती की पद्धति में रासायनिक पध्दाथों का प्रयोग वर्जित है। प्राकृतिक खेती में केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं व संसाधनों का ही प्रयोग होता है। आधुनिक खेती या रासायनिक खेती प्रकृति के खिलाफ है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों से हमारे खेतों की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और जैव तत्त्व मर रहे हैं और वह बंजर हो जाती है। कुदरती खेती प्रकृति के साथ होती है। यद्यपि प्राकृतिक खेती की शुरूआत जापान के कृषि वैज्ञानिक फुकुओवा ने की है लेकिन हमारे यहां भी ऐसी खेती होती रही है। मंडला के बैगा आदिवासी बिना जुताई की खेती करते हैं जिसे झूम खेती कहते हैं।

भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले के एक फार्म मे लगभग पिछले 25 वर्षों से प्राक्रतिक खेती, जिसे कुदरती खेती भी कहते है, हो रही है। करीब 12 एकड़ के इस फार्म में सिर्फ 1 एकड़ में खेती की जा रही है। यहां बिना जुताई (नो टिलिग) और रासायनिक खाद के खेती की जा रही है। बीजों को मिट्टी की गोली बनाकर बिखेर दिया जाता है और वे उग आते हैं। यह सिर्फ खेती की एक पद्धति भर नहीं है बल्कि जीवनशैली है। यहां का अनाज, फल पानी और हवा शुध्द है। यहा कुआं है, जिसमें पर्याप्त पानी है। बिना जुताई के खेती मुश्किल है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। पहली बार सुनने पर विश?वास नहीं होता लेकिन देखने के बाद सभी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। दरअसल, इस पर्यावरणीय पद्धति में मिट्टी की उर्वरता उत्तारोतर बढ़ती जाती है।

बाकी के 11 एकड़ में सुबबूल (आस्टेलियन अगेसिया) का जंगल है। सुबबूल एक चारे की प्रजाति है। इस जंगल से मवेशियों का चारा और लकड़ियां मिल जाती हैं। लकड़ियों की टाल है, जहां से जलाऊ लकड़ी बिकती हैं, जो फार्म की आय का मुख्य स्रोत है। एक एकड़ जंगल से हर वर्ष करीब ढाई लाख रूपये की लकड़ी बेच लेते हैं।

गेहूं के खेतों में हवा के साथ गेहूं के हरे पौधे लहलहाते हैं। खेत में फलदार और अन्य जंगली पेड़ हैं जिनके नीचे गेहूं की फसल होती है। आम तौर पर खेतों में पेड़ नहीं होते हैं लेकिन यहां अमरूद, नीबू और बबूल के पेड़ हैं जिन के कारण खेतों में गहराई तक जड़ों का जाल बुना रहता है। इससे भी जमीन ताकतवर बनती जाती है। अनाज और फसलों के पौधे पेड़ों की छाया तले अच्छे होते हैं। छाया का असर जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर करता है। चूंकि यहां जमीन की उर्वरता अधिक है, इसलिए पेड़ों की छाया का फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।

इन खेतों में पुआल, नरवाई, चारा, तिनका व छोटी-छोटी टहनियों को पड़ा रहने देते हैं, जो सड़कर जैव खाद बनाती हैं। खेत में तमाम छोटी-बड़ी वनस्पतियों के साथ जैव विविधताएं आती -जाती रहती हैं। और हर मौसम में जमीन ताकतवर होती जाती है। इस जमीन में पौधे भी स्वस्थ और ताकतवर होते हैं जिन्हें जल्द बीमारी नहीं घेरती।

यहां जमीन को हमेशा ढककर रखा जाता है। यह ढकाव हरा या सूखा किसी भी तरह से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस ढकाव के नीचे अनगिनत जीवाणु, केंचुए और कीड़े-मकोड़े रहते हैं और उनके ऊपर-नीचे आते-जाते रहने से जमीन पोली और हवादार व उपजाऊ बनती है।

आमतौर पर किसान अपने खेतों से अतिरिक्त पानी को नालियों से बाहर निकाल देते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाता। बारिश में कितना ही पानी गिरे, वह खेत के बाहर नहीं जाता। खेतों में जो खरपतवार, ग्रीन कवर या पेड़ होते हैं, वे पानी को सोखते हैं। इससे एक ओर खेतों में नमी बनी रहती है, दूसरी ओर वह पानी वाश?पीकृत होकर बादल बनता है और बारिश में पुन् बरसता है। इसके विपरीत, जब जमीन की जुताई की जाती है और उसमें पानी दिया जाता है तो खेत में कीचड़ हो जाती है। बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता और तेजी से बहता है। पानी के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस तरह हम मिट्टी की उपजाऊ परत को बर्बाद कर रहे हैं और भूजल का पुनर्भरण भी नहीं कर पा रहे हैं। साल दर साल भूजल नीचे चला जा रहा है।

यहां खेती भोजन की जरूरत के हिसाब से होती हैं, बाजार के हिसाब से नहीं। जरूरत एक एकड़ से ही पूरी हो जाती है। यहां से अनाज, फल और सब्जियां मिलती हैं, जो परिवार की जरूरत पूरी कर देती हैं। जाड़े मे गेहूं, गर्मी में मक्का व मूंग और बारिश में धान की फसल ली जाती है। कुदरती खेती में भूख मिटाने के साथ समस्त जीव-जगत के पालन का विचार है। इससे मिट्टी-पानी का संरक्षण होता हैं। इसे ऋषि खेती भी कहते हैं क्योंकि ऋषि मुनि कंद-मूल, फल और दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, बहुत कम जमीन पर मोटे अनाजों को उपजाते थे। वे धरती को अपनी मां के समान मानते थे, उससे उतना ही लेते थे जितनी जरूरत थी। अत- कुदरती खेती का यह प्रयोग सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

संक्षिप्त समाचार

मूसलाधार बारिश से कलियालिंगुड में आवास का आंगन ध्वस्त

स्याल्दे (अल्मोड़ा)। बीते बुधवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने स्याल्दे विकासखंड के कई गांवों में नुकसान पहुंचाया। दूरस्थ ग्राम पंचायत कलियालिंगुड़ में कमला देवी पत्नी स्व. बालम सिंह के मकान का आंगन का आगे का हिस्सा भारी बारिश के कारण ढह गया। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान पूजा देवी और प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को घटना की जानकारी देकर नियमानुसार क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की। लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है।

खतरनाक मोड़ ठीक करने से ग्रामीणों को मिली राहत

स्याल्दे (अल्मोड़ा)। खलडुवा मार्ग पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे खतरनाक तीखे मोड़ (बैंड) के कटान का कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) विभाग का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मोड़ के सुधार की मांग की जा रही थी जिसके पूरा होने से अब आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। खलडुवाझनागचूलाखाल ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष हरी दत्त बलोदी ने कहा कि विभाग ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए समय पर कार्रवाई की है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम होगी और वाहन चालकों के साथ-साथ राहगीरों को भी राहत मिलेगी। समिति के उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत प्रतिनिधि बाला दत्त शर्मा, समाजसेवी एवं मीडिया प्रभारी हरी सिंह रावत, सुरेंद्र पोखरियाल, खीमानंद नैनवाल और दिनेश लोहनी ने भी पीएमजीएसवाई विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

खेल मैदान के लिए तालाब पाटने का आरोप

सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। विकासखंड सोमेश्वर की ग्राम सभा रैत में निर्माणाधीन खेल मैदान को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि निर्माण स्थल पर पिछले चार-पांच दिनों से एक मृत मवेशी पड़ा है जिसे अब तक नहीं हटाया गया। इससे दुर्गंध फैलने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी पैदा हो गया है।

ग्रामीण नंदन सिंह राणा का कहना है कि जिस स्थान पर खेल मैदान बनाया जा रहा है, वहां करीब 50 वर्ष पुराना तालाब था जिसका उपयोग ग्रामीण और मवेशी करते थे। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान तालाब को मलबा डालकर पाट दिया गया। वहीं हरीश सिंह राणा और सुंदर सिंह राणा ने निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रिया की जांच कराने तथा पर्यावरण और स्थानीय हितों का ध्यान रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृत मवेशी को तत्काल हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

प्रशासन ने तीन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर करवाया शिफ्ट

नई टिहरी। जिला मुख्यालय स्थित सी ब्लॉक टाइप-3 आवासीय परिसर की सुरक्षा दीवार का निर्माण धीमी गति से होने के कारण भवन संख्या-4 में रह रहे तीन परिवारों को खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भवन खाली कराकर परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। एसडीएम टिहरी कमलेश मेहता ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर संवेदनशील भवन पर खतरे का चिह्न लगाया गया है। ठेकेदार को ढाल पर तिरपाल व रेत के थैलों से सुरक्षा व्यवस्था करने व पुलिस को बैरिकेडिंग कर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने लोक जीवन व सुरक्षा को उत्पन्न खतरे के मामले में पुलिस को जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। भवन स्वामी बलवीर सिंह नेगी और सतीश उनियाल ने प्रशासन एवं पुनर्वास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी खतरे से अवगत कराया गया था। बताया कि भवन उनका स्थायी आवंटित आवास है और फिलहाल वे मजबूरी में पूर्व मंत्री दिनेश धनाई के मकान में शरण लिए हुए हैं जबकि उनका सामान अभी भी भवन में रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसूखदारों को भूमि आवंटन किए जाने से कॉलोनी की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। निरीक्षण के दौरान एडीएम शैलेंद्र नेगी, खनन अधिकारी रवि नेगी और आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट भी मौजूद रहे।

तीन साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा

आदिबदरी। तहसील के ताल-कांसुवा राजजात मार्ग के निर्माण के लिए काटे गए खेतों का मुआवजा न मिलने से भूस्वामियों में आक्रोश है। सात किलोमीटर ताल-कांसुवा मोटर मार्ग बने तीन साल से अधिक हो गए लेकिन अभी तक ग्रामीणों को इसका मुआवजा नहीं दिया गया है।लोक निर्माण विभाग गौचर डिवीजन की ओर से निर्मित यह मार्ग हरगांव, मैरोली, मंडल गांव, माधो घाट और कांसुवा से गुजरता है। इन गांवों के अधिकांश काश्तकारों को अभी तक मार्ग के लिए ही गई जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। कांसुवा के क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपेंद्र कुंवर और प्रताप सिंह कुंवर ने बताया कि मुआवजे के संबंध में कई बार विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं। वहीं हरगांव के दिलवर कुंवर और मंडल गांव के त्रिलोक कुंवर ने भी मुआवजे के भुगतान न होने की बात कही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी यदि शीघ्र मुआवजा नहीं मिला तो वे प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोनिवि गौचर के ईई सुनील कुमार ने बताया कि कई भूमिधरों को मुआवजा दे दिया गया है। छूटे हुए भूमिधरों को भी जल्द मुआवजा दिया जाएगा।

विषाक्त मशरूम खाने से पांच लोग बीमार

उत्तरकाशी। भटवाड़ी विकासखंड में मानसून के दौरान विषाक्त मशरूम खाने से पांच लोग बीमार पड़ गए। सभी मरीजों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से सभी मरीजों की हालत फिलहाल सामान्य है। इनमें से तीन मरीज अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं जबकि दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार, भटवाड़ी ब्लॉक के क्यार्क गांव के तीन लोगों ने जंगल से लाए गए मशरूम का सेवन किया था। भोजन करने के कुछ समय बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी। परिजनों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं भटवाड़ी के मल्ला गांव के एक व्यक्ति और टिहरी गढ़वाल निवासी एक अन्य व्यक्ति भी विषाक्त मशरूम खाने के कारण बीमार हो गए। सभी का जिला अस्पताल में उपचार किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 36 वर्षीय मुकेश बुटोला, 35 वर्षीय सतवीर सिंह राणा और 42 वर्षीय राकेश पंवार, तीनों निवासी क्यार्क (भटवाड़ी), 38 वर्षीय यशवीर निवासी मल्ला गांव व 35 वर्षीय अनिल सिंह निवासी टिहरी गढ़वाल शामिल हैं। चिकित्सकों ने लोगों से मानसून के मौसम में जंगलों में उगने वाले अज्ञात मशरूम का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई जंगली मशरूम जहरीले होते हैं ।

दीपा माई पंपिंग योजना ने बुझाई 5 हजार लोगों की प्यास

स्याल्दे (अल्मोड़ा)। विकासखंड स्याल्दे के छह से अधिक गांवों के लिए दीपा माई पंपिंग पेयजल योजना वरदान साबित हो रही है। करीब 8,60,29,000 की लागत से तैयार हुई इस योजना से वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे पांच हजार से ज्यादा लोगों को अब नियमित पेयजल मिलने लगा है। इस योजना के तहत केदार स्थित रामगंगा नदी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए योजना के अंतर्गत 11 स्टोरेज टैंक (जलाशय) बनाए गए हैं। इनकी कार्यक्षमता आगामी 30 वर्षों तक की आबादी की जरूरतों को पूरा करने का अनुमान है। इसके अलावा इस पंपिंग योजना का सीधा लाभ चचरोटी, खटलगांव, सटेड, खटलगैर, सदीगांव और नेवल गांव सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है।

कई अन्य पेयजल योजनाओं पर भी काम तेज

स्याल्दे विकासखंड में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कई अन्य बड़ी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं। इनमें चचरोटी पेयजल योजना का पुनर्गठन, सदे महर गांव पंपिंग पेयजल योजना, झिलगाड़ पंपिंग योजना, सुरगढ़ी पंपिंग पेयजल योजना शामिल हैं।

इनके अलावा जल निगम की ओर से छोटे ग्रामीण इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नई पेयजल योजनाओं की कार्ययोजना (प्रपोजल) भी तैयार की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि इन योजनाओं के पूरे होते ही पूरे विकासखंड में पानी का नेटवर्क मजबूत होगा और ग्रामीणों को स्थायी राहत मिलेगी।

घर छोड़कर घांघरिया पहुंचा बिहार का युवक

ज्योतिर्मठ। घर छोड़कर घांघरिया पहुंचे बिहार के एक युवक को पुलिस ने रातभर अभियान चलाकर सकुशल खोज निकाला। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर युवक को उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार बिहार के पटना निवासी अतुल आनंद (26) घर छोड़कर कही चला गया। उसने पिता को फोन कर बताया कि वह उत्तराखंड में है और अब घर नही आएगा। उसके बाद युवक ने फोन बंद कर दिया। परिजनों को तकनीकी जानकारी से युवक की लोकेशन घांघरिया क्षेत्र में मिली। इसकी जानकारी तुरंत घांघरिया चौकी को दी गई। पुलिस ने रातभर घांघरिया व गोविंदघाट के होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं आदि जगह पर उसकी तलाश की। काफी देर बाद पुलिस ने अतुल को ढूंढ लिया। सूचना पर उसके परिजन बिहार से गोविंदघाट कोतवाली पहुंचे। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : रेखा

सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। सोमेश्वर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बृहस्पतिवार को अपने निजी आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के विकास और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी सोमेश्वर की जनता भाजपा को अपना समर्थन देगी।

बैठक के दौरान ग्राम प्रधान सुंदर सिंह राणा, बालम राम, प्रकाश राम, ललित मिश्रा, अमिताभ रौतेला, कान्हा, महेंद्र सिंह और विनोद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह राणा, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, मंडल महामंत्री कृष्णा भंडारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर बिष्ट, भूपाल मेहरा, वसंत कैड़ा, कमल गिरी आदि मौजूद रहे।

ऑल वेदर रोड प्रभावितों को मुआवजे की उम्मीद

बड़कोट। ऑल वेदर रोड परियोजना से प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-134 के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से बाहर स्थित 16 क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की संयुक्त स्थलीय जांच पूरी कर ली गई है। अब जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद चार करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे का रास्ता साफ होने की संभावना है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति ने बृहस्पतिवार को प्रभावित परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया।

जांच में भवनों में आई दरारें, क्षति के कारणों, निर्माण स्थिति, स्लोप फेल्योर और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया गया। इसमें प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से तथ्यों का सत्यापन किया। धरासू बैंड से फूलचट्टी तक सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित करीब डेढ़ दर्जन मामलों का निस्तारण लंबे समय से लंबित था। एसडीएम बड़कोट और एसडीएम डुंडा की अध्यक्षता में गठित समिति ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत जांच पूरी की। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता मनोज रावत ने बताया कि प्रभावित मामलों के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

यमुनोत्री हाईवे पर स्यानाचट्टी में दूसरे दिन भी आवाजाही ठप रही

उत्तरकाशी। जनपद में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों पर भूस्खलन के कारण आवाजाही बंद होने का सिलसिला थम नहीं रहा। यमुनोत्री हाईवे दूसरे दिन भी स्यानाचट्टी के पास दिनभर यातायात के लिए बाधित रहा। वहीं गंगोत्री हाईवे नालूपानी और लालढांग में सुबह घंटों आवाजाही के लिए बंद रहे। बारिश के चलते जनपद के आठ ग्रामीण मोरटरमार्ग भी बाधित पड़े हैं।

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्यानाचट्टी के समीप बीते बृहस्पतिवार दोपहर से यातायात पूरी तरह बाधित पड़ा है। शुक्रवार को भी दिनभर वहां पर एनएच की मशीनरी हाईवे को खोलने में जुटी रही, लेकिन पहाड़ी से लगातार दरकते चट्टानी मलबे के कारण हाईवे को यातायात के लिए बहाल नहीं किया जा सका। मौके पर मशीनरी लगातार हाईवे को खोलने में जुटी है। इसी तरह गंगोत्री हाईवे सुबह चार घंटे नालूपानी के पास बाधित रहा। जबकि पूर्वाह्न में एक घंटे बंद रहा। गंगोत्री राजमार्ग लालढांग के पास पत्थर गिरने के कारण सुबह बाधित रहा, लेकिन जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया था।

वहीं, आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार, जनपद में बारिश से पीएमजीएसवाई की पांच सड़कें बंद पड़ी हैं। इनमें आराकोट-चिवां, पुरोला-खलाड़ी, चिवां-मोंडा, बरनाली झोटाड़ी और नैटवाड़-नुराणू मोटरमार्ग शामिल हैं। उधर, लोनिवि बड़कोट की चार सड़कें भी आवाजाही के लिए बंद पड़ी हैं। इनमें डामटा-कंडारी, कुवां-कफनौल, बिजोरी-भौंटी मोटरमार्ग अवरूद्ध पड़े हैं। इन सड़कों पर बोल्डर और मिट्टी पत्थर गिरने के कारण आवाजाही बाधित है।

मांगों के लिए प्राथमिक शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन

उत्तरकाशी/पुरोला। टीईटी से छूट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग के संबंध में पुरोला में प्राथमिक शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने और एनपीएस समाप्त कर ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई।

वहीं, जिला मुख्यालय में शाखा भटवाड़ी के शिक्षकों ने तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

शुक्रवार को भटवाड़ी शाखा अध्यक्ष यशपाल राणा और महामंत्री शरत महर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। इसलिए सरकार को ओपीएस को जल्द बहाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी की बाध्यता समाप्त करने की भी मांग उठाई। कहा कि उनकी दोनों मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को इन पर जल्द निर्णय लेकर समाधान करना चाहिए। इस मौके पर राजाराम नौटियाल, जय सिंह चौहान, राघवेंद्र उनियाल, दिनेश चौहान, वीरेंद्र सिंह, आनंद नेगी, कमलेश पुरी, विमला बगियाल, नौबर सिंह कठैत आदि मौजूद रहे। उधर, पुरोला में शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ने केंद्र सरकार से नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) समाप्त कर सभी शिक्षकों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की। इस मौके पर शाखा पुरोला के अध्यक्ष त्रेपन सिंह रावत, सुरेंद्र चौहान, दलबीर रावत, सुखदेव नौडियाल, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पयाल, रघुबीर रावत, बृजमोहन सजवाण, बिजेंद्र रावत, बिंद्रा ठाकुर, कविता जैन, सुरेश शाह, मनोहर पंवार, कुलवंती, रजनी रावत आदि मौजूद रहीं।

पॉलिटेक्निक गैरसैंण और कुलसारी में 95 फीसदी सीटें खाली

कर्णप्रयाग। राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण और कुलसारी में प्रथम काउंसिलिंग के बाद अभी तक अधिक संख्या में सीटें रिक्त हैं। दोनों संस्थानों में 95 फीसदी से अधिक सीटें खाली हैं। ऐसे में छात्र-छात्राएं इन संस्थानों में आसानी से प्रवेश ले सकते हैं। गैरसैंण पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में केवल एक प्रवेश हुआ है जबकि कुलसारी में सिविल में छह और कंप्यूटर साइंस में तीन सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब द्वितीय काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। राजकीय पॉलीटेक्निक कुलसारी में वर्तमान में सिविल और कंप्यूटर साइंस ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान में दोनों ट्रेडों के लिए 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं जबकि गैरसैंण में इलेक्ट्रिकल और सीएस ट्रेड संचालित किए जाते हैं। यहां दोनों ट्रेडों में 32-32 सीटें निर्धारित हैं। संस्थान में प्रथम काउंसिलिंग के बाद कुलसारी पॉलीटेक्निक में सिविल में छह और कंप्यूटर साइंस में तीन सीटों पर ही आवेदन आए हैं जबकि पॉलिटेक्निक गैरसैंण में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में केवल एक प्रवेश हो पाया है। संस्थान के अनुसार अंतिम काउंसिलिंग में ही अधिकतर सीटों पर आवेदन होता है। कुलसारी पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य महेंद्र टम्टा ने बताया कि संस्थान में द्वितीय काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। काउंसिलिंग कराकर छात्र-छात्राएं यहां आसानी से प्रवेश ले सकते हैं।

टीईटी परीक्षा अनिवार्यता समाप्त करने की शिक्षकों ने मांग उठाई

चंबा (टिहरी)। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन चंबा शाखा के शिक्षकों ने ब्लॉक मुख्यालय चंबा में टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया।

उन्होंने उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन के संरक्षक उतम सिंह तोपवाल ने कहा कि शिक्षक लंबे समय टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने और ओपीएस लागू करने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश बना है। कहा कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर शिक्षकों ने ब्लॉक मुख्यालय चंबा में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर शीघ्र मांगों के निराकरण करने की मांग की है। कहा कि जल्द शिक्षकों की मांगों का समाधान नहीं किया जाता है, तो 17 जुलाई को शिक्षक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मांगों को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर दिनेश कुमार, विजय कुमार जोशी, विनोद नेगी, अनिल बधानी, मंगत नेगी, फुरकाना, अतुल प्रकाश चमोली, फते सिंह, अनिल बधानी, विनोद सेलुरियाल, सोबती डोभाल, रजनी थपलियाल, रेशमा, दीपका आर्य, राकेश चौहान, मो यूनुस, कुंवर मखलोगा, गोविंद रावत, नरेश पाल,विजय सिंह, मुजदा खातून, आनंदी चौहान आदि मौजूद थे।

बौराड़ी में लोनिवि मार्ग पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान

नई टिहरी। मास्टर प्लान सिटी बौराड़ी सेक्टर 8 बी में लोक निर्माण विभाग मार्ग पर हो रहे जल भराव से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में डीएम को ज्ञापन भेरा है। बसाया कि चार-पांच सालों से बनी इस समस्या का अभी तक कोई समधान नहीं हो पाया है। सड़क पर पानी भरने से जहां लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल बना हुआ है। वहीं बरसात का पानी कई घरों में भी घुस रहा है। इससे परेशान लोगों ने जल भराव की समस्या से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है।

बौराड़ी लोनिवि मार्ग पर मिलन केंद्र के आस-पास बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बरसात के मौसम में इस मार्ग से पैदल आवागमन करना मुश्किल हो जाता है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेज बारिश में अधिक पानी भरने पर कई बार सड़क का पानी आस-पास निवासरत लोगों के घरों में घुस जाता है। स्थानीय निवासी राजेश तोपवाल और आशा तोपवाल ने डीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि सड़क पर बरसात का पानी जमा होने पर कई बार उनके घरों में घुस जाता है। जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पानी भरने पर वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका और लोनिवि के चक्कर काटने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने डीएम को दिए पत्र में कहा कि 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो उन्हें कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा।

सदस्यों ने लोनिवि की जारी निविदाओं के लिए समिति के गठन की मांग उठाई

नई टिहरी। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सड़क, आपदा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा और पेयजल समेत कई जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने लोनिवि प्रांतीय खंड बौराड़ी की निविदाओं में कथित अनियमितताओं और चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग उठाई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नियमावली तैयार करने की जानकारी दी गई। उपाध्यक्ष मान सिंह रौतेला द्वारा उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। सदस्य दर्शनी रावत ने जिला योजना में उपेक्षा और लोनिवि के पूल्ड हाउस कार्यों की जांच की मांग की। इस दौरान लोनिवि अधिकारी से नोकझोंक के बाद दर्शनी रावत, अनुज शाह, देवेंद्र भट्ट और कविता ने नारेबाजी कर विरोध जताया। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने 30 जुलाई तक जिला योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।सदस्य विजया देवी ने लंबगांव-कंडियालगांव, लक्ष्मी पंवार ने देवल सड़क, विजयपाल रावत ने सेमंडीधार अतिथि गृह का संचालन सहकारी समिति को देने, उत्तम असवाल ने नमामि गंगे के बावजूद देवप्रयाग में गंगा में सीवर मिलने और अनुज शाह ने भिलंगना के 12 जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठाया। विक्रम घाणता ने हिंदांव पट्टी में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की। बैठक में मौजूद घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए लोनिवि अधिकारियों को स्यूरी और गोज्याणा सड़क का प्रस्ताव दोबारा शासन को भेजने के निर्देश दिए। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन में विभागीय समन्वय पर जोर दिया, जबकि अध्यक्ष इशिता सजवाण ने सदन में उठाए गए सभी मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के आवेदनों की समीक्षा

नई टिहरी। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त होमस्टे लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की जिला स्तरीय समिति की ओर से जांच की गई। डीएम ने आवेदकों से संवाद कर उनकी कार्ययोजना, प्रस्तावित होमस्टे, कक्ष निर्माण, कक्षों की मरम्मत, होटल और होमस्टे निर्माण संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। डीएम ने कहा कि चयनित लक्ष्य के तहत सभी आवेदक जिला पंचायत से समन्वय स्थापित कर आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूर्ण करें जिससे योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने जिला पंचायत को भी सभी प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने और आवेदकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में आवेदक चंबा से प्रवीण कोठारी, नैनबाग से सुल्तान सिंह, थत्यूड़ से शोभना देवी, सोनी देवी, संजीत सिंह, सजनु सिंह,बलदेव सिंह, भिलंगना से रेवल सिंह, थौलधार से मनदीप सिंह, प्रतापनगर से किशन सिंह, चंबा से प्यार सिंह आदि ने अपने प्रस्तावों के तहत कक्ष निर्माण, कक्षों के नवीनीकरण , होटल और होमस्टे निर्माण के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र उनियाल स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।

CONT. 9412081969
PRGI NO. 35469/79

13 चौके, 23 छक्के, 55 गेंद, नाबाद 206 रन

अंग्रेज बल्लेबाज का टी20 में दोहरा शतक, टीम ने खड़ा किया 417 रन का स्कोर

नई दिल्ली। भारतीय टीम इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इसी बीच इंग्लैंड में ही एक क्लब टी20 मैच में डम्बलटन क्रिकेट क्लब की टीम ने 417 रन का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। प्रीमियर वन टॉप टियर डिवीजन के टी20 मैच में यह रिकॉर्ड बना। इस मैच में डम्बलटन क्लब के बल्लेबाज इवान गेग ने दोहरा शतक भी लगाया। उन्होंने 55 गेंद में 206 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 23 छक्के लगाए।

इस टूर्नामेंट में डम्बलटन क्रिकेट क्लब की टीम ने हेदरली एंड रेडिंग्स क्लब के खिलाफ मुकाबले में 417 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस दौरान 22 चौके और 47 छक्के डम्बलटन की पारी में लगे। टीम की ओर से सिर्फ चौके छक्कों से ही 370 रन बने। इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए हेदरली की टीम 188 रन से मैच हार गई और 229 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में कुल तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाए। डम्बलटन की तरफ से एक दोहरा शतक और एक शतक लगा। ओपनर इवान गेग ने 206 रन की पारी खेली। वहीं उनके साथी डेन हॉलैंड ने 37 गेंद में 122 रन की पारी खेली। वहीं 418 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हेदरली एंड रेडिंग्स की टीम की तरफ से हैरी ब्लूमफील्ड ने भी 109 रन की पारी खेली। उन्होंने 48 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और 12 छक्के लगाए।

● **टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर–** टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो जिम्बाब्वे के नाम सर्वाधिक 344/4 रन का विशाल स्कोर दर्ज है। जिम्बाब्वे ने जाम्बिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड स्कोर 2024 में बनाया था। जबकि टी20 क्रिकेट में एक टीम के सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बड़ौदा का है। बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ 2024 में 5 विकेट पर 349 रन बनाए थे। टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात करें तो यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है जिसने 304 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में बनाए थे।

फ्रांस ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

एम्बाप्पे ने की मेसी की बराबरी

नई दिल्ली। बोस्टन के जिलेट स्टेडियम में खेले गए 2026 फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले के गोलों की बदौलत फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से करारी शिकस्त दी। फ्रांस लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। कतर में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था। एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में पहला गोल किया।

इसके ठीक छह मिनट बाद डेम्बेले ने दूसरा गोल करके फ्रांस की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले हाफ में एम्बाप्पे ने पेनल्टी को गोल में बदलने से चूक गए, लेकिन इससे उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे हाफ में एक शानदार गोल किया और फिर उस्मान डेम्बेले को असिस्ट भी किया। इस गोल के साथ, एम्बाप्पे आठ गोलों के साथ लियोनेल मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

इंग्लैंड से पहली बार टी20 सीरीज हारा भारत

7 साल बाद लगातार दो सीरीज हारे विश्व विजेता

नई दिल्ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार मैच हार रही है। इंग्लैंड ने शुक्रवार (10 जुलाई) को चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने पहली बार दो या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में भारत को हराया है।

भारत ने पिछले छह में से पांच सीरीज जीते हैं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। मार्च में लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से पहले आयरलैंड से 2 मैचों की टी20 सीरीज हारी। इससे पहले भारतीय टीम फरवरी 2019 में लगातार 2 टी20 सीरीज हारी थी। न्यूजीलैंड ने उसे 1-2 और ऑस्ट्रेलिया ने उसे 2-0 से हराया था। मौजूदा सीजन से पहले भारत ने अपनी पिछली 12 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में से 11 में जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।

इंग्लैंड से 2018 के बाद सीरीज हारी भारतीय टीम

भारतीय टीम 2018 में इंग्लैंड दौरे पर 2 सीरीज हारी थी। वनडे में में 2-1 और टेस्ट में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच खेली गई किसी भी प्रारूप की सीरीज भारतीय टीम नहीं हारी थी। वह 10 में से 8 सीरीज जीती थी। इंग्लैंड में खेली गईं पिछली 2 टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रहीं।

इंग्लैंड की दूसरी बड़ी जीत– भारत ने चौथे टी20 में 37 गेंद रहते 9 विकेट से जीत हासिल की। 150 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए यह इंग्लैंड की विकेट के हिसाब से संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में 192 रनों के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल किया था।

इंग्लैंड ने नौ विकेट से हराया

3-0 से बनाई अजेय बढ़त

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में हुआ। इंग्लैंड ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत को 9 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर

पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर मुकाबला जीत लिया। फिल साल्ट ने 59 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 79 रन बनाकर शानदार अर्धशतक जड़े। इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली है और 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

श्रेयस अय्यर ने तोड़ा रोहित शर्मा और एमएस धोनी का रिकॉर्ड

● **ब्रिस्टल में टॉस जीतते ही किया कमाल**

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से टॉस जीता। बतौर भारतीय कप्तान उन्होंने लगातार अपना छठा टॉस जीता और रोहित शर्मा व एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में भले अभी तक पहला मैच नहीं जीता है लेकिन वह एक भी टॉस अभी तक नहीं हारे हैं। श्रेयस अय्यर ने इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भी दोनों मैचों में टॉस जीता था। वह मौजूदा इंग्लैंड सीरीज में भी पहले चारों मैच में टॉस जीते हैं। उन्होंने बतौर कप्तान लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में विराट कोहली (6) की बराबरी की है। वह अब लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय कप्तान बने हैं।

लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान

● 7 : एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012) ● 6 : विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019) ● 6* : श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026) ● 5 : रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022) ● 5 : एमएस धोनी (सितंबर 2007)

वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में अब तक का प्रदर्शन

5 छक्के, 27 गेंद, 42 रन

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज खास नहीं रहा है। इंग्लैंड में खेली पहली तीन पारियों में लगातार वह फेल ही साबित हुए हैं। उन्होंने पहली तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन ही बनाए हैं। अभी तक लगातार उनकी आईपीएल वाली कमजोरी ही इंग्लैंड में उजागर हुई है। वह तीनों मुकाबलों में शॉर्ट बॉल के सामने दिक्कत में दिखे हैं। पिछली दोनों पारियों में वह शॉर्ट पिच डिलीवरी पर ही आउट हुए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड सीरीज में अभी तक तीन पारियों में 42 रन ही बनाए हैं। उन्होंने 27 गेंद का सामना किया है जिसमें 5 छक्के और सिर्फ एक चौका उनके बल्ले से निकला है। मगर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत शॉर्ट बॉल की समस्या नहीं दूर हो रही है। जोफ्रा आर्चर ने लगातार दूसरी बार वैभव का विकेट झटका है।

उन्होंने ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में 10 गेंद पर 15 रन ही बनाए हैं। इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए मैनचेस्टर में उन्होंने 12 गेंद पर 14 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी में नॉटिंघम में वह 13 रन ही बना पाए थे। नॉटिंघम के बाद ब्रिस्टल में भी वह आर्चर का शिकार बने हैं। आर्चर के खिलाफ वैभव ने 3 पारियों में 13 गेंद पर सिर्फ 18 रन ही बनाए हैं और दो बार उनका शिकार भी वह बने हैं।

वैभव सूर्यवंशी की जगह पर मंडराया खतरा?

भारतीय टीम ने तीन महीने पहले विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन को बाहर करते हुए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह दी थी। अब वैभव ने पहली तीनों पारियों में निराश किया है। उनके अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं।

वैभव को जितनी तेजी से टीम में लाने की मांग उठ रही थी। उतनी तेजी से ही अब उनकी खामियां सामने आ रही हैं। इसी कारण सीरीज के आखिरी मुकाबले में अब उनकी जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने पहली तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बनाए हैं। उनका इंटरनेशनल डेब्यू खास नहीं रहा है। अब आखिरी टी20 में उनकी जगह संजू सैमसन की एंट्री होती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

भारत ने गंवाई यूथ वनडे सीरीज

रोमांचक मैच में 1 विकेट से जीता श्रीलंका, अंतिम 10 ओवर में ठोके 76 रन

नई दिल्ली। श्रीलंका की अंडर-19 टीम ने हम्बनटोटा में खेले गए तीसरे यूथ वनडे में भारतीय टीम को एक विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने 2-1 से यूथ वनडे सीरीज अपने नाम की। हम्बनटोटा के महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

इंडिया -19 टीम ने वीके विनीत के शतक की मदद से 50 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका -19 ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 291 रन बनाकर मैच और सीरीज अपने नाम की। चार जून 2026 को इसी मैदान पर खेले गए पहले यूथ वनडे इंटरनेशनल को इंडिया -19 ने 4 विकेट से जीता था, लेकिन छह जुलाई को हुए दूसरे वनडे

इंटरनेशनल में उसे आठ विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

तीसरे यूथ वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो श्रीलंका -19 का 40 ओवर में स्कोर आठ विकेट पर 215 रन था। श्रीलंका -19 को 10 ओवर में 76 रन बनाने थे और उसके सिर्फ दो विकेट गिरना शेष थे। इसके बाद चमिका हीनतिगाला और गिम्हन मेंडिस ने नौवें विकेट के लिए 47 गेंद में 61 रन की साझेदारी की। गिम्हन मेंडिस 22 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए।

चमिका हीनतिगाला सात चौके और दो छक्के की मदद से 68 गेंद में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका -19 की ओर से सेनूजा वेकुनागोडा ने भी अर्धशतक लगाया। सेनूजा वेकुनागोडा ने 10 चौके और एक छक्के की मदद से 59 गेंद में 67 रन की पारी खेली। इंडिया -19 की ओर से अनमोलजीत सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे।

अनमोलजीत सिंह ने 8 ओवर में 42 रन देकर चार विकेट लिए। शाविन विनोद 10 ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे। मोहित उल्वा ने भी दो विकेट लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने नौ ओवर में 66 रन दे डाले।

30 पदकों का बड़ा झटका

कुश्ती-बैडमिंटन समेत 6 खेलों के हटने से भारत की मेडल उम्मीदों पर संकट

नई दिल्ली। बर्मिंघम 2022 के खेलों में इन हटाए गए खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 30 पदक (13 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य) जीते थे, जो भारत के पूरे 61 पदकों का लगभग आधा हिस्सा है। यह नुकसान भारत के लिए नया नहीं है, बल्कि पिछले कई संस्करणों का इतिहास बताता है कि इन खेलों को हटाने से भारत को हमेशा बड़ा आर्थिक व खेल-कूद का नुकसान उठाना पड़ा है।

● **कुश्ती :** बर्मिंघम 2022 में भारत ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित 12 पदक हासिल किए थे। अगर पीछे देखें, तो गोल्ड कोस्ट 2018 खेलों में भी भारतीय पहलवानों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक देश की झोली में डाले थे।

● **बैडमिंटन :** साल 2022 में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग की जोड़ी के दम पर भारत ने 3 स्वर्ण समेत 6 पदक हासिल किए। इससे पहले 2018 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण (मिक्सड टीम और सायना नेहवाल), 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते थे। 2014 में भी बैडमिंटन से 1 स्वर्ण (पारुपल्ली कश्यप), 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक आए थे।

● **टेबल टेनिस :** बर्मिंघम 2022 में टेबिल टेनिस में अचंत शरद कमल के नेतृत्व में पैरा-इवेंट्स को मिलाकर 4 स्वर्ण समेत 7 पदक आए।

● **हॉकी और स्क्वैश :** बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, जबकि हॉकी में 2 पदक (1 रजत, 1 कांस्य) और स्क्वैश में 2 कांस्य पदक भारत के नाम रहे।